राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, गुरुवार, 30 अप्रैल 2026

वर्ष 14, अंक 20, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

मलिहाबादः दबंगई की हद पार.....03

आंध्र प्रदेश में खुलेगा गूगल डेटा सेंटर....04

भड़काऊ भाषण को लेकर दायर सभी याचिकाएं खारिज, सुप्रीम कोर्ट

» सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो कानून मौजूद वो काफी
» बेंच ने साफ किया कि हेट स्पीच से जुड़े कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, न कि अदालतों के पास
» बेंच ने कहा, 'भले ही संवैधानिक अदालतें कानून की व्याख्या कर सकती हैं
» मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश भी जारी कर सकती हैं, लेकिन वे खुद कानून नहीं बना सकतीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज बुधवार को हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण को लेकर दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. साथ ही कोर्ट ने पूरे देश में हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण पर रोक लगाने के लिए और निर्देश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने इसकी वजह यह बताई कि मौजूदा कानून ही इसके लिए काफी है. कोर्ट का कहना है कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह संबंधित हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने फैसले की कॉपी को हर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष भेजने का निर्देश भी दिया. जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला सुनाया. बेंच ने अपने फैसले में कहा कि किसी काम को अपराध घोषित करने का अधिकार पूरी तरह से विधायिका (कानून बनाने वाली संस्था) के दायरे में आता है।

'कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते'

कोर्ट ने अपने फैसले में आगे साफ करते हुए कहा कि संवैधानिक अदालतें कानून की व्याख्या तो कर सकती हैं, लेकिन वे कानून बनाने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकतीं. कोर्ट का कहना है कि हेट स्पीच से जुड़ा क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां कोई कानून मौजूद न हो. इस बारे में इस तरह की चिंताएं उठती हैं, वे कानून की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कानून को ठीक से लागू नहीं किए जा सकने की वजह से उठती हैं।

बीएनएसएस के तहत बनाए गए कानूनों का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'बीएनएसएस के तहत तैयार किया गया कानूनी ढांचा, आपराधिक कानूनों को अमल में लाने का एक पूरा और व्यापक तरीका देता है. इसलिए, कानून के मामले में यहां किसी तरह का कोई खालीपन (विधायी निर्वात) नहीं है. इसी तरह सीआरपीसी की धारा 156(3) जो अब ब्नहस्स् की धारा 175 (3)] हो गई, के तहत मजिस्ट्रेट के पास निगरानी का जो अधिकार है, उसका दायरा बहुत बड़ा है।

'कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास'

कोर्ट ने कहा, 'किसी मामले में आगे बढ़ने से पहले 'मंजूरी' लेने की जो शर्त है, वह तभी लागू होती है जब कोर्ट मामले का स्वतः संज्ञान लेता है. यह शर्त, संज्ञान लेने से पहले के चरण पर, या स्नढ्ढक्र दर्ज करने पर, या बीएनएसएस की धारा 175(3), पहले सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत की जाने वाली जांच पर लागू नहीं होती।

बेंच ने यह साफ किया कि हेट स्पीच से जुड़े कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, न कि अदालतों के पास. बेंच ने कहा, 'भले ही संवैधानिक अदालतें कानून की व्याख्या कर सकती हैं. लोगों के मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए निर्देश भी जारी कर सकती हैं, लेकिन वे खुद कानून नहीं बना सकतीं और न ही कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकती हैं. कोर्ट ज्यादा से ज्यादा, कानून में सुधार की जरूरत की ओर ध्यान दिला सकती हैं. लेकिन, कानून बनाया जाए या नहीं, और अगर बनाया जाए तो किस तरह से बनाया जाए, इस बारे में फैसला लेने का अधिकार पूरी तरह से संसद और राज्यों की विधानसभाओं के पास ही रहता है।

हेट स्पीच के संबंध में आदेश पारित करने से इनकार करते हुए, कोर्ट ने कहा, 'हम यह कहना उचित समझते हैं कि हेट स्पीच और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईचारे, गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने से जुड़े हैं.' कोर्ट ने कई याचिकाओं के एक ग्रुप पर फैसला सुनाया, जिनकी शुरुआत 2020 की घटनाओं से हुई थी. तब कई याचिकाएं दायर की गई थीं जिनमें आरोप लगाया गया था कि प्रसारण मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सांप्रदायिक नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं।

कोर्ट ने कहा कि अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वह संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सकता है. साथ ही कोर्ट ने फैसले की कॉपी को हर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष भेजने का निर्देश दिया।

'किन्नर' बिरादरी को 'बधाई' या 'नेग' मांगने का अधिकार नहीं... एच.सी.

» बोला- यह अपराध माना जा सकता है
» एक किन्नर की याचिका को खारिज करते हुए एच सी ने कहा कि ऐसी याचिका को मंजूरी देने का मतलब होगा कि अवैध वसूली को कानूनी मान्यता मिल जाएगी
» जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. इस तरह की वसूली को कानून ने कभी भी सही नहीं ठहराया है

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कल मंगलवार को अपने अहम फैसला में कहा कि 'किन्नर' समुदाय के लोगों के पास पारंपरिक 'बधाई' या 'नेग' (शुभ मौकों पर दी जाने वाली नकद भेंट) मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की मांग करना भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध मानी जा सकती हैं। लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय ने यह आदेश गोंडा जिले की एक ट्रांसजेंडर, रेखा देवी की ओर से दाखिल एक रिट याचिका को खारिज करते हुए दिया. रेखा देवी ने अपनी याचिका में 'नेग' पाने के लिए एक खास इलाके को खुद के लिए आरक्षित करने की मांग की थी।

याचिकाकर्ता ने जगह तय करने की रखी थी मांग

याचिकाकर्ता ने जरवल कस्बे में 'काटी का पुल' से लेकर 'घाघरा घाट' और कर्नलगंज में 'सरयू पुल' तक के इलाके को अपने लिए खास क्षेत्र के तौर पर आरक्षित करने की मांग की थी. उसका दावा था कि वह कई सालों से इन जगहों से 'नेग' लेती रही हैं. उसके वकील ने कोर्ट में यह दलील दी कि जब उसके समुदाय के दूसरे लोग इस इलाके में आते हैं, तो अक्सर झगड़े और झड़प की घटना हो जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही प्रथा एक पारंपरिक अधिकार बन चुकी है। हालांकि कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. अपने फैसले में कोर्ट ने कहा कि कोई भी लेवी, टैक्स या फीस सिर्फ कानून के अधिकार के तहत ही एकत्र की जा सकती है. 'बधाई' या 'जजमानी' के नाम पर पैसे लेने की प्रथा को कानून की कोई मंजूरी नहीं है।

कानून में इस परंपरा का प्रावधान नहीं: एच.सी.

बेंच ने यह भी कहा, 'किसी भी व्यक्ति से जान-बूझकर या किसी भी तरह से पैसे वसूलने की इजाजत नहीं दी जा सकती. किसी भी नागरिक को सिर्फ वही रकम चुकाने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसे कानून ने सही ठहराया हो.' कोर्ट ने यह भी कहा कि 'ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019' में ऐसे किसी अधिकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

याचिका को खारिज करते हुए बेंच ने कहा कि ऐसी याचिका को मंजूरी देने का मतलब होगा कि अवैध वसूली को कानूनी मान्यता मिल जाएगी, जिससे आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल सकता है. बेंच ने यह भी कहा कि इस तरह की वसूली को कानून ने कभी भी सही नहीं ठहराया है, और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडात्मक प्रावधान भी लागू हो सकते हैं।

संक्षिप्त ख़बरें

लखनऊ में अचानक बदला मौसम, बेटी की आनी है बारात और आंधी में उड़ गया टेंट; खाना भी हुआ बर्बाद

निगोहां (लखनऊ)। गोडियन खेडा के वंशीलाल की बेटी शीलू की बुधवार शाम को बारात आनी है वहीं दिन में आई तेज आंधी और बारिश से टेंट उड़कर क्षतिग्रस्त हो गया, बन रहे व्यंजन भी कुछ बर्बाद हो गए। इस दौरान परिवारीजन काफी परेशान दिखें, ग्रामीणों की मदद से दोबारा टेंट को सही किया।

हाईटेंशन लाइन का खंभा टूटा, सड़क पर गिरा

नगराम मार्ग पर तेज हवाओं के चलते हाईटेंशन लाइन का खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। रास्ता बंद होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिजली विभाग और प्रशासन को अवगत करा दिया गया है। मौके पर खतरे की स्थिति बनी हुई है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। जेई आशीष ने बताया कि मौके पर टीम को भेजा गया है, खंभे को हटवाया जा रहा है।

अवर अभियंता की तीन मई को मुख्य परीक्षा, केंद्रों की सूची जारी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से अवर अभियंता (सिविल) और सहायक विकास अधिकारी (सिविल) भर्ती की मुख्य परीक्षा तीन मई को आयोजित की जा रही है। इसके लिए आयोग ने परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी है और एडमिट कार्ड भी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए हैं। यह परीक्षा कुल 4612 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है, जिसका विज्ञापन वर्ष 2023-24 में जारी हुआ था। परीक्षा के लिए पीलीभीत, संतकबीरनगर, शामली, अमरोहा, भदोही, बागपत, कन्नौज और कानपुर देहात जिलों में केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा का निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है, वे अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी केंद्रों की विस्तृत सूची भी वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है।

मौत की सजा पर SC ने निचली अदालतों को दिए निर्देश, सजा के कारकों पर रिपोर्ट जरूर मांगे

» सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मृत्युदंड के मामलों में निचली अदालतों को सजा सुनाने से पहले सजा कम करने और बढ़ाने वाले कारकों पर रिपोर्ट मंगानी होगी. कोर्ट ने मौजूदा प्रवृत्ति पर चिंता जताई जहां शुरुआती चरणों में ऐसी रिपोर्ट नहीं ली जाती है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मृत्युदंड की संभावना वाले मामलों में सजा सुनाने से पहले निचली अदालतों को सजा कम करने वाले और बढ़ाने वाले कारकों पर रिपोर्ट मंगानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शुरुआती चरण में ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने में विफलता संतुलित सजा प्रक्रिया को कमजोर करती है और सुधारात्मक कारकों पर सार्थक विचार में देरी करती है।

जस्टिस विक्रम नाथ जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील की सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किया. सुप्रीम कोर्ट ने अपीलों की सुनवाई और अंतिम निपटारे तक मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगाई है।

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि हमें कई मामलों में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखने को मिल रही है. जिन मामलों में मौत की सजा हो सकती है, वहां शुरुआती चरणों में ही सजा घटाने या बढ़ाने वाली परिस्थितियों पर रिपोर्ट नहीं मंगाई जाती है. यह जरूरी कदम न तो ट्रायल कोर्ट में सजा सुनाते समय उठाया जाता है और न ही हाईकोर्ट में सजा की पुष्टि के लिए भेजे जाने के दौरान

इस चूक के कारण एक बेहद अजीब स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी अहम जानकारी पहली बार सिर्फ इस कोर्ट (सुप्रीम कोर्ट) के सामने अपील के दौरान मांगी जाती है. इस वजह से सजा के सवाल पर सही समय पर और पूरी सोच-समझकर फैसला लेने के लिए जरूरी जानकारी जुटाने में काफी देरी हो जाती है. साथ ही, इसमें अनावश्यक अंतराल भी आ जाता है।

जब इन पहलुओं पर देर से विचार किया जाता है, तो सज़ा देने की एक संतुलित प्रक्रिया का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। इससे सुधार (रिफॉर्म) से जुड़े सिद्धांतों को सही तरीके से लागू करने में भी रुकावट आती है।

सजा कम करने वाले कारकों जानें

सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई में ये भी बताया कि मनोज और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में यह निर्देश दिया गया था कि निचली अदालतों को मृत्युदंड लगाने से पहले सजा कम करने वाले कारकों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. कोर्ट ने पाया कि शुरुआती चरण में ऐसी रिपोर्ट न मिलने से सजा सुनाने की संतुलित प्रक्रिया कमजोर होती है और सुधार से जुड़े कारकों पर सही ढंग से विचार करने में देरी होती है. मौत की सज़ा वाले मामलों में व्यवस्थागत खामियों को उजागर करते हुए कोर्ट ने पाया कि ऐसे कई मामलों में आरोपियों को दी जाने वाली कानूनी मदद का स्तर अपर्याप्त रहता है, जिसके कारण कार्यवाही के अहम चरणों में कानूनी प्रतिनिधित्व असरदार नहीं हो पाता।

सीतापुर में तीन शवों के गांव पहुंचते ही मचा कोहराम, एक ही चिता पर मां-बेटे का हुआ अंतिम संस्कार

सीतापुर। अरथाना में शाम को चार बजे हिमांशु, रेखा व सुनीता के शव पहुंचे तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। रेखा व पुत्र हिमांशु को एक ही चिता पर मुखाग्नि दी गई। यह देखकर सभी की आंखें नम थीं। वहीं, सुनीता का अंतिम संस्कार सोमवार सुबह होना तय है। सुनीता अपनी बेटी सौम्या की शादी खोज रही थीं। पति जयशंकर बिसवां चीनी मिल में सुरक्षा गार्ड हैं। छोटा बेटा आदर्श प्राइवेट नौकरी करता है। सुनीता के परिवार में सोमवार को चंद्र प्रकाश की बेटी की शादी व पड़ोस के जितेंद्र का तिलक समारोह है। हादसे के बाद शादी का माहौल गम में डूब गया है। घटना से पूरा गांव सदमे में है।

मातम में बदलीं खुशियां, जल्दी विदा हुई बरात महोली: लखीमपुर के बगहा निवासी सत्येंद्र कुमार अपनी पत्नी सरिता व भाभी मैना देवी के साथ शनिवार शाम पाल्हापुर में अपने मौसा छत्रपाल वर्मा की पौत्री के विवाह कार्यक्रम में आए थे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद देर रात12 बजे अपने घर बगहा के लिए निकल गए।

सीतापुर में शराब के नशे में बारातियों ने दौड़ाई कार, महिला की मौत; शादी भी टूटी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सिधौली (सीतापुर)। हैदरगढ़ पुरवा में रविवार को वैवाहिक समारोह में डीजे म्यूजिक पर डांस करने और भोजन की गुणवत्ता को लेकर जनाती-बारातियों में विवाद और मारपीट हो गई। इस दौरान बराती अपने-अपने वाहन लेकर भागने लगे। इसमें एक बराती की कार से कुचलकर शादी में शामिल होने आई महिला की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया। शादी भी टूट गई। बताया जा रहा है अधिकांश बराती शराब के नशे में थे। पुलिस ने पांच नामजद समेत अज्ञात पर मुकदमा लिखा है।

हैदरगढ़ पुरवा के राजकुमार के यहां पहुंची थी बरात

लखनऊ के शिवलोक त्रिवेणीनगर तृतीय मुहल्ले से श्याम बिहारी के बेटे संजय की बरात हैदरगढ़ पुरवा के रामकुमार के यहां रविवार को आई थी। मध्य रात नशे में धुत युवा डांस करने की जिद करने लगे। इस पर जनातियों और बरातियों में कहासुनी हुई। बड़े-बुजुर्गों के दखल से प्रकरण शांत हो गया। इसके बाद बरातियों को भोजन परोसा गया। भोजन ठंडा होने की बात कहकर वह झगड़ने लगे। कुछ ही समय में दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी।

बराती की कार की चपेट में आकर महिला घायल

बराती अपने-अपने वाहन लेकर भागने लगे। इसी दौरान एक बराती की कार की चपेट में आने से शादी में शामिल होने आए अटरिया के उमरा के शोभेलाल और बख्शी तालाब की कांती घायल हो गईं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली ले लाया गया, जहां से कांती को लखनऊ और शोभेलाल को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कांती की सोमवार को इलाज के दौरान ट्रामा सेंटर में मौत हो गई। वहीं, शोभेलाल का इलाज चल रहा है। पुलिस ने श्याम बिहारी, उनके बेटे संजय, गुड्डू व रितेश (पता अज्ञात) और सिधौली के गोलू पर मुकदमा लिखा गया है।

तिनका-तिनका जोड़कर की व्यवस्था, एक झटके में हो गई बर्बाद

रामकुमार किसान हैं। उन्होंने तिनका-तिनका जोड़कर बेटी की शादी के लिए व्यवस्था की थी। ग्रामीणों के मुताबिक बरातियों की नशेबाजी के चलते उनकी व्यवस्थाएं एक झटके में बर्बाद हो गईं। इसको लेकर रामकुमार परेशान हैं।

पान-मसाला खाया तो कटेगी जेब, यूपी की इस मशहूर यूनिवर्सिटी में अब शिक्षकों और अफसरों पर भी लगेगा 500 का जुर्माना

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों, शिक्षकों से लेकर अधिकारियों तक यदि पान, मसाला, खुटखा या मादक पदार्थ का सेवन करते पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कुलसचिव डा. भावना मिश्रा की ओर से बुधवार को जारी आदेश के अनुसार अक्सर देखने में आया है कि विश्वविद्यालय परिसर में कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों द्वारा पान, मसाला, गुटखा एवं मादक पदार्थ आदि का सेवन किया जाता है जो कार्यालय की मर्यादा, गरिमा एवं कर्मचारी शिक्षक आचरण नियमावली के विरुद्ध है। इसलिए परिसर में इसका सेवन करते पाए जाने पर 500 रुपये संबंधित पर जुर्माना लगेगा। यदि किसी शिक्षक, कर्मचारी या अधिकारी द्वारा तीन बार से अधिक पान, मसाला, गुटखा या मादक पदार्थ का सेवन करते पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।

हाईस्कूल में टॉप करने वाली प्राची निगम का क्या रहा इंटर का रिजल्ट?

सीतापुर। सीता बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद की छात्रा प्राची निगम ने वर्ष 2024 में यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में सीतापुर का नाम रोशन करते हुए पूरे प्रदेश में टॉप किया था। रिजल्ट आने के बाद जब उनकी फोटो इंटर मीडिया पर वायरल हुई, तो कुछ लोगों ने उनके चेहरे के बालों (मूंछों) को लेकर उनका भद्दा मजाक उड़ाकर ट्रोल किया था। प्राची ने इंटरमीडिएट परीक्षा में भी शानदार प्रदर्शन कर उन्होंने 91.20 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं। अंग्रेजी विषयों को छोड़कर उन्होंने अन्य सभी विषयों में उनको अच्छे अंक मिले हैं। अंग्रेजी में उनके 73 अंक ही आ पाए। गणित में 99, हिंदी में 96, रसायन विज्ञान में 95 और भौतिक विज्ञान में 93 अंक प्राप्त किए हैं। अगर अंग्रेजी में प्राची के 90 प्रतिशत से अधिक अंक आ जाते तो वह एक बार फिर मेरिट में स्थान बनाती। मजाक उड़ाए जाने पर प्राची ने बहुत ही परिपक्वता से जवाब दिया था। उन्होंने कहा था -अगर मेरे चेहरे पर बाल न होते तो शायद मैं टॉप न करती। मेरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर था, अपने लुक पर नहीं। लोगों का काम कहना है, लेकिन मेरी सफलता मेरी पहचान है। अब भी उनका लक्ष्य बदला नहीं है। प्राची आईआईटी से इंजीनियर बनना चाहती हैं। वह इस सपने को पूरा करने की तैयारी में जुटी हुई हैं। जब उनका मजाक उड़ाया गया, तब देश के कई बड़े नामों ने उनके समर्थन में ट्वीट किए थे। प्राची ने बताया कि शक्ल में नहीं अक्ल में विश्वास करती हैं। बताया, आइआइटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी के चलते वह अंग्रेजी विषय पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाई। यही वजह रही कि उनके नंबर कम हो गए।

प्रवेश परीक्षा में टॉप करने का जुनून

प्राची को मेरिट लिस्ट में स्थान न बनाने का अफसोस है, लेकिन उनका हौसला कमजोर नहीं है। बताया, उतार-चढ़ाव तो जीवन का हिस्सा है। इंटरमीडिएट के परिणाम को उन्होंने इसी तरह से लिया है। वह पूरी क्षमता के साथ आइआइटी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। बताया, वह प्रवेश परीक्षा में टाप करके इंजीनियर बनकर देश सेवा करेंगी।

बेंगलुरु में आफत की बारिश, बोरिंग अस्पताल के पास दीवार ढही; सात की मौत... रेस्क्यू जारी

» बेंगलुरु में तेज बारिश के दौरान बोरिंग अस्पताल परिसर का हिस्सा ढहने से 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हैं. मलबे में और लोगों के दबे होने की आशंका के बीच राहत-बचाव कार्य जारी है

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मंगलवार शाम हुई तेज बारिश के बीच बड़ा हादसा हो गया। शिवाजीनगर स्थित बॉरिंग और लेडी कर्जन अस्पताल के पास एक कंपाउंड की दीवार अचानक भरभराकर ढह गई, जिसमें सड़क किनारे मौजूद दुकानदारों और राहगीरों समेत 7 लोगों की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी और लोग दबे हो सकते हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

तेज बारिश के बीच हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, शाम करीब 5 बजे से शुरू हुई बारिश करीब एक घंटे तक तेज हवाओं, गरज और ओलों के साथ जारी रही. अचानक बिगड़े मौसम से बचने के लिए सड़क किनारे मौजूद लोग और बच्चे अस्पताल परिसर के पास शरण लेने लगे. इसी दौरान एक कंपाउंड की दीवार का हिस्सा भरभराकर गिर गया और वहां मौजूद लोग उसकी चपेट में आ गए।

घायलों का इलाज जारी

हादसे में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल की इमरजेंसी में इलाज चल रहा है. वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मुख्यमंत्री ने किया निरीक्षण

घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. उन्होंने अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली और परिसर के अचानक ढहने पर नाराजगी जताते हुए जिम्मेदारों को फटकार लगाई. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मृतकों के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए की मुआवजे की घोषणा की. वहीं उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने भी घटनास्थल का दौरा कर राहत-बचाव कार्यों की समीक्षा की।

राजनीतिक प्रतिक्रिया और अपील

इस हादसे पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी एमएलसी सी.टी. रवि ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतकों की संख्या 8 से 10 के बीच हो सकती है और आगे बढ़ने की आशंका है. उन्होंने कहा कि इस आपदा के लिए किसी को दोषी ठहराने के बजाय सरकार को पीड़ितों के साथ खड़ा होना चाहिए. फिलहाल प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. लगातार बारिश के कारण हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है।

मजदूरः शहरों का ढांचा बुनने वाले, फिर भी हाशिए पर खड़े सपने

[शहर के बाहर खड़े असली निर्माता– जिनके बिना स्मार्ट इंडिया भी अधूरा]
[धूल, पसीना और सपनाः मजदूर की वो कहानी जो नीतियों को शर्मिंदा करती है]

भोर की पहली किरण जब शहर की नींद पर धीरे से दस्तक देती है, उसी समय किसी निर्माण स्थल पर हथौड़े की चोटें नए कल की नींव रखने लगती हैं। यह ध्वनि केवल पत्थर नहीं तराशती, बल्कि उस भविष्य को गढ़ती है जिसे हम विकास के नाम से पहचानते हैं। धूल से सने, छालों से भरे ये हाथ ही वे अदृश्य निर्माता हैं, जिनकी मेहनत से कांच जैसी ऊँची इमारतें, चौड़ी सड़कों की रेखाएँ और उड़ान भरते एयरपोर्ट खड़े होते हैं। सुबह पाँच बजे चाय की भाप के बीच वे अपने बच्चों के सपनों को संवारते हैं, जबकि स्वयं शहर की रोशनी से दूर, तिरपाल के साए में रातें काटते हैं। उनकी थकान ही उनकी ताकत है–जीने की, बनाने की और टूटे सपनों को फिर से खड़ा करने की अदम्य जिद। 1 मई इस सच्चाई का स्मरण कराता है कि जिनके हाथों से दुनिया बनती है, उनकी आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकती–वह हर युग में उठती है और व्यवस्था की नींव हिला देने का सामर्थ्य रखती है।

ये मजदूर जिसे हम 'अनस्किल्ड' कहकर खारिज करते हैं, दरअसल सबसे जरूरी स्किल रखते हैं – वो स्किल जो मशीनें अभी सीख नहीं पाई। ये लोग बिना तकनीक के भी प्रकृति के संकेत पहचान लेते हैं, सीमित संसाधनों में समाधान खोज लेते हैं और छोटी-सी सजगता से बड़े जोखिम टाल देते हैं। शहरों की ऊँचाइयाँ इन्हीं के परिश्रम से आकार लेती हैं, फिर भी वे व्यवस्था के किनारों पर ही खड़े रह जाते हैं। कोई तपती सड़क पर डिलीवरी करता है, कोई आग की लपटों में वेल्डिंग कर भविष्य गढ़ता है, तो कोई दूसरों के घरों में सेवा देकर जीवन को सहारा देता है। उनकी पहचान फिर भी केवल 'मजदूर' तक सिमटी रहती है। वास्तव में वे समाज की रीढ़ हैं–जिनके बिना आधुनिकता का ढांचा ढह सकता है, और अगर ये हाथ थम जाएँ तो स्मार्ट सिटी का सपना भी बिखर जाएगा।

विकास की ऊँचाइयों पर खड़ा आज का भारत, उन्हीं श्रमिक हाथों की नींव पर टिका है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हालिया आंकड़े बताते हैं कि अनौपचारिक क्षेत्र लगभग 12.81 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देता है, जबकि निर्माण क्षेत्र में 90 प्रतिशत से अधिक कार्यबल असंगठित है। करीब 15 करोड़ प्रवासी मजदूर अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं और अनौपचारिक क्षेत्र कुल जीडीपी का लगभग 50 प्रतिशत योगदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल पर 31 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। ये केवल आँकड़े नहीं, बल्कि उन अनगिनत कहानियों की गवाही हैं जहाँ पेट भरने के लिए कोई बिहार से दिल्ली, कोई उत्तर प्रदेश से मुंबई पहुँचता है। उनकी निःशब्द मेहनत ही देश की प्रगति का असली आधार है। अब एआई का युग है। हम स्मार्ट सिटी, ऑटोमेशन और रोबोटिक्स की बात करते हैं, लेकिन एआई भी कहीं न कहीं श्रमिकों की स्किल पर ही निर्भर है। यह डिजाइन बना सकता है, ड्रोन नियंत्रित कर सकता है और डिलीवरी मार्ग सुधार सकता है, पर ईंट उठाना, वेल्डिंग करना या कठिन परिस्थितियों में काम पूरा करना आज भी मनुष्य के ही बस की बात है। एआई गिग वर्कर्स को बेहतर अवसरों से जोड़ रहा है और 2026 तक एआई-आधारित गिग अर्थव्यवस्था के 335 बिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। फिर भी, एआई थकान का अनुमान लगा सकता है, पर वह वह धैर्य और जिद नहीं दे सकता जो एक मजदूर बारिश में भी काम करते हुए दिखाता है। एआई मजदूरों का विरोधी नहीं, बल्कि सही उपयोग होने पर उनका सहयोगी बन सकता है।

मजदूरों का संघर्ष अब केवल वेतन या कार्य-घंटों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सम्मान, सुरक्षा और सुरक्षित भविष्य की लड़ाई बन चुका है। गिग अर्थव्यवस्था में काम करने वाले लाखों युवा तपती धूप और ठंडी रातों में सेवाएँ देते हैं, फिर भी उन्हें पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती। महिलाएँ घरेलू कार्य से लेकर निर्माण स्थलों तक अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, लेकिन समान अवसर और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अभी भी गंभीर कमी है। 1 मई 2026 इन्हीं प्रश्नों–महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय–पर केंद्रित है। इतिहास साक्षी है कि मजदूरों की एकजुटता ने बदलाव रचे हैं, चाहे 1886 का शिकागो हो या आज का भारत। उनकी चुप्पी भी एक गहरा प्रश्न छोड़ती है–क्या उनकी भागीदारी के बिना प्रगति संभव है?

हमें ऐसे समाज की आवश्यकता है जहाँ मेहनत को किसी वर्ग या दर्जे से नहीं, बल्कि उसके वास्तविक मूल्य और गरिमा के आधार पर देखा जाए। जहाँ कोई बच्चा अपने पिता को मजदूर कहकर शर्मिंदा न हो, बल्कि पूरे गर्व से उनका सम्मान करे। नीतियाँ ऐसी हों कि एआई मजदूरों का सशक्त सहायक बने–उन्हें ऑनलाइन कौशल प्रशिक्षण, वास्तविक समय सुरक्षा निगरानी और न्यायसंगत आय की सुनिश्चितता दे। निर्माण स्थलों पर एआई-सहायता प्राप्त आधुनिक उपकरण श्रम का बोझ भले हल्का करें, लेकिन आत्मसम्मान और गौरव को कभी कम न करें। जब तक उनकी मुस्कान विकास की मुख्यधारा का हिस्सा नहीं बनती, तब तक हर उपलब्धि अधूरी ही रहेगी।

श्रम की धड़कनों से गढ़ी यह दुनिया किसी एक दिन की पहचान नहीं मांगती, बल्कि निरंतर सम्मान चाहती है। इस 1 मई को केवल अवकाश न समझें, बल्कि उन हाथों को महसूस करें जो ईंट-पत्थर जोड़कर हमारे सपनों के शहर बनाते हैं। उनकी जीवन-कहानियों को सुनें, उनकी आवाज़ को मंच दें और उनके परिश्रम को वह स्थान दें जो वास्तव में उनका अधिकार है। वे लोग जो शहरों की परछाइयों में रहकर भी राष्ट्र की प्रगति का भार उठाते हैं, असली निर्माता वही हैं। जब हर श्रमिक का सम्मान समाज की ऊँचाई बनेगा, तभी विकास का अर्थ पूर्ण और सार्थक होगा। यह दिन हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन की सबसे बड़ी शक्ति श्रम के मौन पसीने में छिपी होती है।

कृति आरके जैन

भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौताः किसानों, व्यापारियों, युवाओं और द्विपक्षीय संबंधों के लिए नए अवसरों का युग

भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) केवल एक आर्थिक करार नहीं है, बल्कि यह दोनों देशों के बीच गहरे होते भरोसे, सहयोग और भविष्य की साझा संभावनाओं का प्रतीक भी है। इस समझौते के जरिए न सिर्फ व्यापारिक रिश्तों को नई गति मिलेगी, बल्कि किसानों, व्यापारियों, छात्रों और नौकरीपेशा युवाओं के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे। यह डील ऐसे समय में सामने आई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों से गुजर रही है और देशों के बीच मजबूत साझेदारी की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महसूस की जा रही है। इस समझौते पर भारत की ओर से वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैक्ले ने हस्ताक्षर किए, जबकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने इसे दोनों देशों के लिए ऐतिहासिक बताया। यह समझौता अब न्यूजीलैंड की संसद में अनुमोदन के बाद पूरी तरह लागू होगा, लेकिन इसके संभावित प्रभाव अभी से चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। एफटीए के तहत न्यूजीलैंड भारतीय निर्यात पर लगभग सभी टैरिफ समाप्त कर देगा, जिससे भारतीय उत्पाद वहां सस्ते और अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे। इसके जवाब में भारत भी न्यूजीलैंड से आने वाले लगभग 95 प्रतिशत उत्पादों पर शुल्क में भारी कमी करेगा। इस तरह यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले पांच वर्षों में दोनों देशों ने व्यापार को 5 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान स्तर की तुलना में एक बड़ा उछाल होगा। इस समझौते का सबसे बड़ा लाभ भारत के उन क्षेत्रों को मिलेगा जो निर्यात पर निर्भर हैं। रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते, समुद्री उत्पाद, आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और हस्तशिल्प जैसे सेक्टर न्यूजीलैंड के बाजार में बिना शुल्क के प्रवेश कर सकेंगे। इससे भारतीय उत्पादों की मांग बढ़ेगी और देश के एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिलेगी। छोटे और मध्यम उद्योग, जो अक्सर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं, उन्हें इस डील के जरिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहचान बनाने का मौका मिलेगा। किसानों के लिए भी यह समझौता राहत लेकर आया है। हालांकि भारत ने डेयरी, कॉफी, मसाले, खाद्य तेल और कुछ अन्य संवेदनशील कृषि उत्पादों को इस समझौते से बाहर रखा है, ताकि घरेलू किसानों को नुकसान न हो। यह एक संतुलित रणनीति है, जिससे जहां एक ओर व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर किसानों के हितों की भी रक्षा होगी। दूसरी तरफ, भारत को न्यूजीलैंड से लकड़ी, कोकिंग कोल और धातु स्क्रैप जैसे औद्योगिक कच्चे माल पर ड्यूटी-फ्री पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिलेगी। यह समझौता केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवा क्षेत्र और मानव संसाधन के आदान-प्रदान को भी बढ़ावा देता है। भारतीय युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर बनकर सामने आया है। इस डील के तहत हजारों भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के लिए अस्थायी वीजा मिलेगा। आईटी विशेषज्ञ, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, योग प्रशिक्षक, शेफ और संगीत शिक्षक जैसे पेशों के लिए नए अवसर खुलेंगे। इससे न केवल युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अनुभव मिलेगा, बल्कि भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। छात्रों के लिए भी यह समझौता बेहद लाभकारी साबित हो सकता है। विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित एसटीईएम विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों को न्यूजीलैंड में पढ़ाई के बाद तीन साल तक काम करने की अनुमति मिलेगी। यह प्रावधान भारतीय छात्रों को वैश्विक शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करेगा। साथ ही, 'वर्क एंड हॉलीडे' वीजा के जरिए युवा पढ़ाई और काम के साथ-साथ विदेश में रहने का अनुभव भी हासिल कर सकेंगे। इस समझौते का असर आम उपभोक्ताओं पर भी दिखाई देगा। न्यूजीलैंड से आने वाले कई उत्पाद जैसे कीवी, सेब, चेरी, ब्लूबेरी और एवोकाडो भारतीय बाजार में सस्ते हो सकते हैं। इसके अलावा, बच्चों के लिए फॉर्मूला मिल्क, कुछ धातु उत्पाद और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतों में भी कमी आ सकती है। हालांकि वाइन जैसे कुछ उत्पादों पर टैरिफ में चरणबद्ध कमी की व्यवस्था की गई है, ताकि घरेलू उद्योग को अचानक प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी यह समझौता सकारात्मक संकेत लेकर आया है। मेडिकल डिवाइस और दवाओं के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे भारतीय कंपनियों को न्यूजीलैंड के बाजार में प्रवेश आसान होगा। इससे लागत कम होगी और दवाओं की उपलब्धता में सुधार आएगा। भारतीय फार्मा कंपनियां, जो पहले से ही वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं, अब इस नए अवसर का लाभ उठा सकेंगी। इस समझौते का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि यह केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों को भी मजबूत करता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच लंबे समय से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, लेकिन यह एफटीए उन संबंधों को एक नई दिशा और गहराई देता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच विश्वास को बढ़ाता है और भविष्य में अन्य क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं को भी मजबूत करता है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और बदलते आर्थिक परिदृश्य के बीच यह समझौता भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह न केवल देश के निर्यात को बढ़ावा देगा, बल्कि रोजगार सृजन, कौशल विकास और आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। साथ ही, यह दिखाता है कि भारत अब वैश्विक व्यापार में अधिक सक्रिय और प्रभावशाली भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारत-न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता एक बहुआयामी पहल है, जो व्यापार, शिक्षा, रोजगार और कूटनीति के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यह समझौता दोनों देशों के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का माध्यम बनेगा और आने वाले वर्षों में इसके दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। **कांतिलाल मांडोत**

तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी असंतोषजनक

[ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण की आवश्यकता।]

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात एआई आज केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक संरचनाओं, आर्थिक अवसरों और शक्ति संतुलन को पुनर्परिभाषित करने वाला परिवर्तनकारी माध्यम बन चुका है। इस परिवर्तन के केंद्र में यदि किसी वर्ग के लिए सर्वाधिक संभावनाएँ छिपी हैं तो वह है महिला वर्ग, क्योंकि सदियों से अवसरों की असमानता, संसाधनों तक सीमित पहुँच और निर्णय-निर्माण में कम भागीदारी जैसी बाधाओं का सामना करने वाली महिलाओं के लिए एआई एक नई ऊर्जा, नई दिशा और नया इम्पैक्ट लेकर आया है।

विश्व स्तर पर उपलब्ध नवीन आँकड़े यह संकेत देते हैं कि तकनीकी क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी अभी भी संतोषजनक नहीं है, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार एआई से जुड़े कार्यक्षेत्रों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 28 से 30 प्रतिशत के बीच है, जबकि नेतृत्वकारी भूमिकाओं में यह प्रतिशत और भी कम हो जाता है, भारत में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 20 प्रतिशत एआई पेशेवर महिलाएँ हैं, परंतु यदि प्रशिक्षण, डिजिटल पहुँच और नीतिगत समर्थन को व्यापक बनाया जाए तो 2027 तक इस संख्या के चार गुना तक बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है। यह आँकड़ा केवल सांख्यिकीय वृद्धि का संकेत नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति संतुलन में संभावित बड़े बदलाव का संकेत है। एआई इम्पैक्ट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह कौशल आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है।

जहाँ पारंपरिक लैंगिक पूर्वाग्रह अपेक्षाकृत कम प्रभावी होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल ट्यूटर, एआई-आधारित भाषा अनुवाद उपकरण और कोडिंग सिमुलेटर उन महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं जो भौगोलिक, सामाजिक या पारिवारिक कारणों से औपचारिक संस्थानों तक नहीं पहुँच पाती थीं। इस संदर्भ मे यूनेस्को ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि एआई को समावेशी दृष्टिकोण के साथ विकसित किया जाए तो यह महिलाओं की कार्यभागीदारी और नेतृत्व क्षमता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा सकता है, इसी प्रकार डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ने अपनी रिपोर्टों में उल्लेख किया है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था में लैंगिक समानता सुनिश्चित करना वैश्विक विकास की अनिवार्य शर्त है।

एआई इम्पैक्ट का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम कार्यस्थल पर महिलाओं की आवाज़ को सशक्त करना है। मीटिंग एनालिटिक्स कंपनी की एक हालिया रिपोर्ट में पाया गया कि एआई-सहायता प्राप्त वर्चुअल मीटिंग टूल्स के उपयोग से महिलाएँ औसतन 9 प्रतिशत अधिक बोलती हैं, क्योंकि एआई आधारित नोट-टेकिंग और समय प्रबंधन उपकरण उन्हें बिना बाधा अपनी बात रखने का अवसर देते हैं।

यह परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं बल्कि संरचनात्मक है, क्योंकि निति-निर्माण में आवाज़ की उपस्थिति ही शक्ति का पहला चरण होती है। ग्रामीण और अर्धशहरी भारत में एआई इम्पैक्ट का एक और आयाम उभर कर आया है जहाँ डिजिटल सखी, एआई चैटबॉट और स्मार्ट कृषि सलाह प्लेटफॉर्म महिलाओं को उद्यमिता की दिशा में प्रेरित कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएँ अब एआई आधारित बाजार विश्लेषण, मूल्य पूर्वानुमान और ग्राहक पहुँच टूल्स का उपयोग कर अपने उत्पादों को व्यापक बाजार तक पहुँचा पा रही हैं इससे आय में वृद्धि के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। यह आर्थिक सशक्तिकरण सामाजिक सशक्तिकरण में रूपांतरित हो रहा है; स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई इम्पैक्ट और भी गहरा है।

मातृ स्वास्थ्य निगरानी, पोषण परामर्श, मानसिक स्वास्थ्य चैटबॉट और प्रारंभिक रोग पहचान प्रणाली ग्रामीण महिलाओं के लिए जीवनरक्षक सिद्ध हो रही हैं, जहाँ पहले विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुँच कठिन थी वहाँ अब मोबाइल आधारित एआई समाधान प्राथमिक मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। इससे स्वास्थ्य असमानताओं में कमी आने की संभावना है; किंतु एआई का यह सकारात्मक पक्ष तभी स्थायी होगा जब इसके नकारात्मक आयामों को भी गंभीरता से समझा जाए, अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि लगभग 40 प्रतिशत एआई मॉडल किसी न किसी रूप में लैंगिक पूर्वाग्रह से प्रभावित होते हैं, यदि प्रशिक्षण डेटा असंतुलित है तो निर्णय भी असंतुलित होंगे, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि डिजिटल हिंसा, डीपफेक और ऑनलाइन उत्पीड़न की घटनाएँ महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं। अनुमान है विश्व की लगभग 38 प्रतिशत महिलाएँ किसी न किसी रूप में ऑनलाइन हिंसा का अनुभव कर चुकी हैं। अतः एआई इम्पैक्ट को सकारात्मक बनाए रखने के लिए सख्त डेटा नैतिकता, एल्गोरिथमिक पारदर्शिता और लैंगिक संवेदनशील नीति ढाँचा अत्यंत आवश्यक है।एआई महिलाओं के लिए केवल नौकरी का साधन नहीं बल्कि नेतृत्व का माध्यम भी बन सकता है। डेटा-आधारित निर्णय प्रणाली राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ा सकती है जिससे महिलाओं की भागीदारी मजबूत हो, जब निर्णय तथ्यों और विश्लेषण पर आधारित होंगे तो पूर्वाग्रहों की गुंजाइश घटेगी, इसके अतिरिक्त फ्रीलांसिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, एआई ट्रेनिंग और माइक्रो-टास्किंग जैसे नए क्षेत्रों ने उन महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता दी है जो पारंपरिक नौकरी संरचना में शामिल नहीं हो पाती थीं।

यह लचीला कार्य-मॉडल मातृत्व और पारिवारिक दायित्वों के साथ संतुलन बनाने में सहायक है। एआई इम्पैक्ट का मनोवैज्ञानिक पहलू भी उल्लेखनीय है, जब महिलाएँ तकनीक की उपभोक्ता मात्र न रहकर उसकी निर्माता और नवोन्मेषक बनती हैं तो आत्मविश्वास और पहचान दोनों का विस्तार होता है, विश्वविद्यालयों और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में महिला सहभागिता बढ़ाने के प्रयास यह संकेत देते हैं कि आने वाले दशक में एआई क्षेत्र में महिला नेतृत्व की नई पीढ़ी उभरेगी; निष्कर्षतः एआई एक दोधारी तलवार अवश्य है परंतु यदि इसे समावेशी नीति, लैंगिक संतुलन, डिजिटल साक्षरता और नैतिक नियमन के साथ आगे बढ़ाया जाए तो इसका इम्पैक्ट महिलाओं के लिए ऐतिहासिक परिवर्तन का माध्यम बन सकता है, यह परिवर्तन केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक, बौद्धिक और राजनीतिक शक्ति संतुलन का परिवर्तन होगा, जहाँ महिला केवल भागीदार नहीं बल्कि निर्णयकर्ता, निर्माता और नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित होगी, और यही एआई की वास्तविक सफलता होगी कि वह तकनीक को मानवता और समानता की दिशा में प्रयुक्त करे, क्योंकि जब महिला सशक्त होती है तो समाज सशक्त होता है और जब समाज सशक्त होता है तो राष्ट्र प्रगतिशील बनता है।

संजीव ठाकुर

कविता

संजीव-नी।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम।

केवल धनुर्धारी वीर नहीं थे,
अवचेतन में धर्म निभाते धीर थे।

राजमहलों का सुख छोड़कर
वनों में मुस्कुराते कर्मवीर थे।

तैयारी थी राज्याभिषेक की,
वहीं कदम बढ़े वन की ओर।

14 वर्ष वनवास बिताया
पितृ आदेश का धर्म निभाया।

शीश पर पितृ धर्म का साया।
निभाई पूरी सृष्टि की मर्यादा,

अपना सुख त्यागकर
कर्तव्य पथ को ही अपनाया।

पत्थरों में भी जीवन देखा,
शबरी के जूठे बेरों में प्रेम,

राजा होकर भी झुके ऐसे,
विनम्रता से हो जिनका प्रेम।

वियोग में भी स्थिर रहे,
सीता जी के संग भी संयम,

राज धर्म मर्यादा में थे बँधे,
जीवन के आदर्शों के संगम।

लक्ष्मण संग
स्नेह की धारा,
भरत के लिए त्याग अपार,

भाईचारे की पवित्र छाया में
खिलता एक निर्मल संसार।

और जब लौटे वे अयोध्या में,
केवल राजा ही नहीं बने

जन-जन के मन में बसने वाले
एक आदर्श,
एक उज्ज्वल प्रतिमान बने।

राम केवल कथा नहीं ,
हैं जीवन का अनुशासन ,

वे मर्यादा के स्पंदन।

मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम,

दिलों में बसने वाले श्री राम।

जय जय श्री राम,जय श्री राम।

संजीव ठाकुर

राजा रवि वर्मा के चित्रों में जीवित गौरवशाली

भारतीय चित्रकला के गौरवशाली इतिहास में राजा रवि वर्मा एक ऐसे युगपुरुष के रूप में प्रतिष्ठित हैं जिन्होंने अपनी कूची और रंगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक नई पहचान और वैश्विक गरिमा प्रदान की। 29 अप्रैल 1848 को केरल के किलिमनूर नामक छोटे से गांव में जन्मे इस महान कलाकार ने उस समय कला की साधना प्रारंभ की जब वह केवल राजदरबारों की दीवारों और प्राचीन मंदिरों के गर्भगृहों तक ही सीमित थी। रवि वर्मा का जन्म एक ऐसे कुलीन परिवार में हुआ था जहाँ कला, साहित्य और संस्कृति का संगम पहले से ही विद्यमान था और इसी वातावरण ने उनकी अंतर्निहित प्रतिभा को पल्लवित होने का सुअवसर प्रदान किया। बचपन से ही उनके हाथों में रंगों और रेखाओं का जो जादू था उसे उनके परिवार ने शीघ्र ही पहचान लिया और उन्हें कला के क्षेत्र में निरंतर प्रोत्साहित किया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के साथ ही चित्रकला का अभ्यास निरंतर चलता रहा और शीघ्र ही उनकी ख्याति त्रावणकोर के महाराजा तक पहुँच गई। महाराजा के संरक्षण ने रवि वर्मा के जीवन को एक निर्णायक मोड़ दिया जहाँ उन्हें न केवल संसाधन उपलब्ध हुए बल्कि वैश्विक कला की बारीकियों को समझने का अवसर भी प्राप्त हुआ।

उस दौर में भारत में तैल चित्रकला की प्रविधि बहुत कम प्रचलित थी और भारतीय कलाकार मुख्य रूप से पारंपरिक शैलियों में ही कार्य कर रहे थे। रवि वर्मा ने यूरोपीय शैली की यथार्थवादी कला का गहराई से अध्ययन किया और उसे भारतीय विषयों के साथ समाहित करने का साहसिक प्रयास किया। उन्होंने अपनी कला में पाश्चात्य प्रविधि और भारतीय आत्मा का जो संगम किया उसने चित्रकला के इतिहास में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया। उनकी कला की सबसे विलक्षण विशेषता यह थी कि उन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं के पात्रों को मानवीय संवेदनाओं के साथ जीवंत रूप में प्रस्तुत किया। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के जो पात्र अब तक केवल कल्पनाओं या पांडुलिपियों के विवरणों तक ही सीमित थे वे रवि वर्मा के चित्रों में हाड़-मांस के मनुष्य की तरह जीवंत होकर सामने आए। उनके द्वारा चित्रित राम, सीता, कृष्ण, द्रौपदी और शकुंतला के चित्रों में भावनाओं की जो गहराई और चेहरों पर जो भाव विद्यमान थे उन्होंने जनमानस के हृदय को स्पर्श किया। विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और सरस्वती के जो स्वरूप उन्होंने अपनी तूलिका से गढ़े वे आज भी करोड़ों भारतीय घरों के पूजा स्थलों में श्रद्धा के साथ देखे जा सकते हैं।

रवि वर्मा की कला का एक महत्वपूर्ण पक्ष भारतीय स्त्री के सौंदर्य और उसकी गरिमा का चित्रण था। उनके चित्रों में स्त्रियां केवल सौंदर्य का प्रतीक मात्र नहीं थीं बल्कि वे भावनात्मक रूप से अत्यंत सशक्त और गरिमापूर्ण दिखाई देती थीं। उन्होंने भारतीय नारी को एक ऐसे आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जिसमें सौम्यता, शक्ति और मर्यादा का अद्भुत संतुलन था। उनके द्वारा चित्रित साड़ी पहने हुए स्त्रियों के चित्रों ने न केवल भारतीय वेशभूषा को एक वैश्विक पहचान दी बल्कि वह भारतीय नारीत्व की एक शाश्वत छवि बन गई। उनके चित्रों में रंगों का चयन और वस्त्रों की सिलवटों का सूक्ष्म चित्रण इतना यथार्थवादी था कि दर्शक उन चित्रों के साथ एक आत्मीय जुड़ाव महसूस करने लगता था। उनकी कला में केवल बाहरी सौंदर्य ही नहीं बल्कि पात्रों की मानसिक अवस्था और उनके अंतर्द्वंद्व को भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। शकुंतला का अपने पैर से कांटा निकालने का बहाना करके पीछे मुड़कर देखना हो या दमयंती का हंस से संवाद, हर चित्र एक पूरी कहानी स्वयं में समेटे हुए था।

भारतीय चित्रकला को महलों से निकालकर झोपड़ियों तक पहुँचाने का श्रेय भी निर्विवाद रूप से राजा रवि वर्मा को ही जाता है। वर्ष 1894 में उन्होंने मुंबई में एक शिलामुद्रणालय अर्थात लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना करके एक क्रांतिकारी कदम उठाया। इस प्रेस के माध्यम से उनके चित्रों की हजारों प्रतियां छपने लगीं और बहुत ही कम मूल्य पर सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध होने लगीं। इससे पहले कला केवल धनी वर्ग और शासकों के विलास का साधन समझी जाती थी परंतु रवि वर्मा ने अपनी इस दूरदर्शिता से कला का लोकतंत्रीकरण कर दिया। उनके द्वारा बनाए गए चित्र कैलेंडरों और पोस्टरों के रूप में प्रत्येक घर की शोभा बनने लगे। इसी माध्यम से भारतीय देवी-देवताओं की एक निश्चित छवि जनमानस के मस्तिष्क में स्थायी रूप से अंकित हो गई। यह उनकी कला का ही प्रभाव था कि उस समय के साधारण भारतीय भी अपनी संस्कृति और धार्मिक प्रतीकों के साथ गर्व से जुड़ सके।

रवि वर्मा की सफलता केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही बल्कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारतीय कला का परचम लहराया। वर्ष 1873 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में उन्हें पुरस्कृत किया गया जिससे उनकी ख्याति विश्वव्यापी हो गई। इसके पश्चात उन्हें भारत की विभिन्न रियासतों जैसे बड़ौदा, मैसूर और उदयपुर के राजाओं का निमंत्रण और संरक्षण प्राप्त हुआ। उन्होंने देश के विभिन्न अंचलों की व्यापक यात्राएं कीं और वहां की विविधतापूर्ण संस्कृति, वेशभूषा और जनजीवन को अपनी कला में स्थान दिया। उनकी इन यात्राओं ने उनकी कला को और अधिक समृद्ध और समावेशी बनाया। हालांकि उनकी इस पाश्चात्य शैली की कुछ पारंपरिक कलाकारों ने आलोचना भी की और इसे भारतीयता के विरुद्ध बताया परंतु समय ने सिद्ध किया कि रवि वर्मा ने वास्तव में भारतीय कला को आधुनिकता के साथ जोड़कर उसे नया जीवन प्रदान किया था।

उनकी कला में छाया और प्रकाश का जो प्रयोग था वह अद्वितीय था। उन्होंने चित्रों में गहराई पैदा करने के लिए जिस सूक्ष्मता से कार्य किया वह आज भी कला के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय है। उनके चित्रों के रंगों में एक ऐसी चमक और स्थायित्व था जो दशकों बाद भी धूमिल नहीं हुआ। वे केवल एक चित्रकार ही नहीं थे बल्कि भारतीय संस्कृति के एक ऐसे दूत थे जिन्होंने विदेशी शासन के दौर में भी भारतीय मूल्यों को गौरव के साथ स्थापित किया। 2 अक्टूबर 1906 को इस महान विभूति का निधन हो गया लेकिन वे अपनी कला के रूप में आज भी अमर हैं। उनकी विरासत आज भी भारतीय चित्रकारों को प्रेरित करती है और उनके बनाए चित्र आज भी विश्व के प्रतिष्ठित संग्रहालयों में सुरक्षित रखे गए हैं। रवि वर्मा का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिभा और समर्पण के माध्यम से सीमाओं को तोड़ा जा सकता है और कला के जरिए समाज में एक व्यापक वैचारिक परिवर्तन लाया जा सकता है।

राजा रवि वर्मा ने कला को केवल मनोरंजन का साधन न मानकर उसे राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का माध्यम बनाया। उनके चित्रों ने उस कालखंड में भारतीयों के भीतर अपनी परंपराओं के प्रति स्वाभिमान जगाने का कार्य किया जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव चरम पर था। उनकी सबसे बड़ी देन यही है कि उन्होंने आम आदमी की आंखों को कला परखने की दृष्टि दी और कला को जन सामान्य की भावना का अभिन्न अंग बना दिया। आज भी जब हम किसी पौराणिक आख्यान की कल्पना करते हैं तो हमारे मन में अनायास ही वही रूप उभरते हैं जिन्हें रवि वर्मा ने अपनी कल्पना से साकार किया था। भारतीय कला के इतिहास में उनका नाम सदैव एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां उनके कार्यों से निरंतर प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी– स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

ई-रिक्शा की छत पर बैठकर ड्रोन से बनाई रील

स्टंट करते चार युवकों का वीडियो वायरल

लालगंज (रायबरेली)। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले युवाओं की लापरवाही सामने आई है। ई-रिक्शा पर स्टंट करते युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। करीब 41 सेकंड के वीडियो में चार युवक नजर आ रहे हैं। दो युवक ई-रिक्शा की छत पर बैठे हैं। दो अन्य आगे लटकते दिख रहे हैं। छत पर बैठा एक युवक ड्रोन कैमरा चलाता दिखाई दे रहा है। युवक चलते ई-रिक्शा पर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया। वायरल वीडियो कोतवाली क्षेत्र के ऐहार गांव के पास का बताया जा रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में नहीं है। वायरल वीडियो मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

लखनऊ में क्रिप्टो में निवेश के नाम पर व्यवसायी से ऐंठे 1.15 करोड़ रुपये, जालसाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज

लखनऊ। साइबर जालसाजों ने क्रिप्टो और एसआइपी में निवेश कराने के नाम पर व्यवसायी राजेंद्र सिंह चौहान से 1.15 करोड़ रुपये ऐंठ लिए। मुनाफा देख रकम निकालने के सोची तो जालसाजों ने ट्रांसफर कराने के नाम पर रकम मांगी थी। तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ।कृष्णानगर थाने में पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। इंस्पेक्टर पीके सिंह के मुताबिक राजेंद्र सिंह चौहान पूरन नगर निवासी है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में उनकी मुलाकात हिमांशु गिहर उर्फ आजाद से हुई थी। हिमांशु ने खुद को एसआइपी निवेश का जानकार बताया था। इसके बाद बातचीत शुरू हो गई। उसने निवेश के नाम पर कई जानकारी दी। इसके बाद दस गुना मुनाफे का लालच देकर विश्वास में लिया। वर्ष 2021 से 23 के बीच 50 लाख से अधिक का निवेश कराया। इतने रुपये निवेश के बाद भी कोई मुनाफे की रकम नहीं मिली। विरोध पर हिमांशु ने बताया कि उसमें घाटा हो गया है। इसके बाद उसने समझाया और क्रिप्टो में निवेश पर मोटे मुनाफे का लालच दिया। इसमें निवेश कराकर सारा घाटा पूरा करने का आश्वासन दिया। वर्ष 2023 से 25 के बीच भी करीब 50 लाख का निवेस कराया। चार वर्ष में हिमांशु ने करीब 1.15 करोड़ रुपये का निवेश कराया और सारी रकम हड़प ली।

केंद्र की मंजूरी के बावजूद यूपी में आलू खरीद में देरी, किसानों को नुकसान

लखनऊ। कीमतें गिरने से नुकसान झेल रहे आलू उत्पादक किसानों को केंद्र सरकार ने तो राहत देने का रास्ता खोल दिया है, परंतु प्रदेश के उद्यान विभाग की सुस्ती इसमें रोड़ा बनी हुई है। केंद्र ने बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत प्रदेश सरकार को 20 लाख टन आलू खरीदने की अनुमति दी है। 650 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों से आलू खरीदने के लिए 203.15 करोड़ रुपये भी आवंटित कर दिए हैं, परंतु इसके सात दिन गुजरने के बाद भी उद्यान एक क्रय केंद्र भी शुरू नहीं कर पाया है। इस साल आलू उत्पादक किसानों को फसल के दाम कम मिलने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते ही केंद्र ने 18 अप्रैल को यह निर्णय लिया है। इसके बाद उद्यान विभाग को आलू उत्पादक क्षेत्रों में क्रय केंद्रों का संचालन कर खरीद करनी है। सूत्रों के अनुसार, उद्यान विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश मंडी परिषद, यूपी एग्रो, उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ (हाफेड) और पीसीएफ के माध्यम से खरीद कराई जानी है। वर्तमान में प्रदेश में 2363 शीतगृह संचालित हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 202.99 लाख टन है। इस साल 6.98 लाख हेक्टेयर में आलू की बोआई हुई थी और लगभग 253 लाख टन उत्पादन हुआ है। वर्तमान में लगभग 90 प्रतिशत आलू आलू शीतगृहों में भंडारित हो चुका है। ऐसे में सरकारी क्रय केंद्र खुलने पर भी किसानों की कम संख्या में पहुंचने की बात कही जा रही है, वहीं जो कीमत सरकार ने तय की है, उससे भी किसानों को बहुत अंतर नहीं पड़ेगा।

सार्वजनिक सूचना

यह सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संपत्ति संख्या प्लॉट संख्या 22 और 23, खसरा संख्या 618Sa का भाग, क्षेत्रफल 1500.00 वर्ग फुट ग्राम बनथरा सिकंदरपुर, परगना महोना, तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ में स्थित से संबंधित पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 24/06/2014, पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 17453, पृष्ठ संख्या 275 से 296, क्रम संख्या 13428 का अंतिम पृष्ठ (दफा 60) कहीं गुम हो गया है, जिसकी सूचना पुलिस यूनिट पुलिस कंप्यूटर सेंटर टेक्निकल सर्विसेज मुख्यालय लखनऊ में एफ.आई.आर संख्या 2026 0000343230 दिनांक 14/ 04/ 2026 को दर्ज कराई गई है।

यदि किसी व्यक्ति को उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई दावा/आपत्ति हो तो इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अधोहस्ताक्षरी से संपर्क करें।

दिनांक: 29/04/2026

नाम: धर्मेन्द्र कुमार पुत्र देवीचरण निवासी बौनामऊ, थाना उन्नाव, उ.प्र. 209801

मोबाइल: 8840445321

मलिहाबाद: दबंगई की हद पार

क्राइम

- युवक पर बाइक से जानलेवा हमला
- हत्या के साये में जी रहे परिवार की पुलिस ने नहीं सुनी गुहार
- पुरानी रंजिश में आदित्य प्रताप सिंह को कुचलने की कोशिश
- फरार आरोपी दे रहा धमकियां
- कार्रवाई न होने से रामपुर बस्ती में ग्रामीणों के बीच भारी रोष!

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मलिहाबाद, लखनऊ। राजधानी के ग्रामीण अंचल मलिहाबाद में कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए दबंगों ने एक बार फिर आतंक का माहौल पैदा कर दिया है। क्षेत्र के रामपुर बस्ती गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर सरेराह जानलेवा हमला किया गया, लेकिन घटना के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस की सुस्ती ने प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार, जो पहले ही अपनों को खोने का गम झेल रहा है, अब पुलिस की निष्क्रियता के कारण खौफ और असुरक्षा के साये में जीने को मजबूर है। मिली जानकारी के अनुसार, रामपुर बस्ती निवासी पीड़ित आदित्य प्रताप सिंह अपने चचेरे भाई के घर के बाहर खड़े थे, तभी गांव के ही दबंग प्रमोद कुमार ने रंजिश के तहत उन्हें जान से मारने की नीयत से अपनी तेज रफ्तार पल्सर बाइक से पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। गनीमत रही कि आदित्य ने ऐन वक्त पर खुद को संभाल लिया, वरना एक बड़ी अनहोनी घट सकती थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि प्रमोद कुमार एक शातिर किस्म का व्यक्ति है जो पूर्व में भी उनके परिवार को फर्जी मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित कर चुका है। आरोप है कि वह आए दिन परिवार को जान से मारने की धमकी देता है और रात के समय अपने संदिग्ध साथियों के साथ गांव के बाहर घेराबंदी करता है, जिससे पूरा परिवार घर से निकलने में भी डर रहा है। इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाला पहलू पुलिस का उदासीन रवैया रहा है। पीड़ित परिवार का कहना है कि हमले की तत्काल सूचना देने के बावजूद पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कोई सक्रियता नहीं दिखाई। गौरतलब है कि पीड़ित के जेठ की पहले ही हत्या हो चुकी है, जिसके बाद से परिवार लगातार न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है। ऐसे संवेदनशील इतिहास के बावजूद पुलिस द्वारा मामले को हल्के में लेना किसी बड़ी घटना को आमंत्रण देने जैसा है।

स्थानीय ग्रामीणों में भी पुलिस के इस ढुलमुल रवैये को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त है। पीड़ित ने अब जिला प्रशासन और उच्चाधिकारियों से मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसके ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के कागजातों की जांच की जाए और उसे तत्काल सलाखों के पीछे भेजा जाए, ताकि गांव में शांति व्यवस्था कायम रह सके और एक निर्दोष परिवार की जान बचाई जा सके।

'उद्योग 4.0: विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के भविष्य का रूपांतरण विषय पर' महत्वपूर्ण आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ- राजधानी लखनऊ के इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), यू.पी. स्टेट सेंटर, लखनऊ द्वारा 'उद्योग 4.0: विनिर्माण और प्रौद्योगिकी के भविष्य का रूपांतरण विषय पर एक' विषय पर एक महत्वपूर्ण तकनीकी व्याख्यान का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल, 2026 को इंजीनियर्स भवन, आई. ई. आई. , रिवर बैंक कॉलोनी, लखनऊ में किया गया। इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉ. अभिषेक कुमार, प्रोफेसर एवं डिप्टी डायरेक्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जी. सी. आर. जी. ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, लखनऊ ने सहभागिता की। अपने व्याख्यान में उन्होंने इंडस्ट्री 4.0 के विभिन्न आयामों, आधुनिक तकनीकों, स्वचालन (Automation), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ते प्रभाव पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हो रहे हैं, जिससे उत्पादन क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में तकनीकी उन्नति के साथ-साथ उद्योगों को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनका समाधान नवाचार, कौशल विकास एवं आधुनिक तकनीकों के समुचित उपयोग से संभव है। कार्यक्रम की अध्यक्षता इं. वी.पी. सिंह, चेयरमैन, आई. ई. आई. यू. पी. स्टेट सेंटर, लखनऊ द्वारा की गई। अपने अध्यक्षीय संबोधन में उन्होंने कहा कि इस प्रकार के तकनीकी व्याख्यान अभियंताओं, विद्यार्थियों एवं उद्योग जगत के लिए अत्यंत उपयोगी हैं और इससे नई तकनीकों के प्रति जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने मुख्य वक्ता का आभार व्यक्त करते हुए संस्था द्वारा ऐसे कार्यक्रमों के निरंतर आयोजन की बात कही। कार्यक्रम के संयोजक इं. विनोद सक्सेना, ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। सफल संचालन एवं समन्वय संस्था के मानद सचिव इं. एन.के. निषाद, द्वारा किया गया। अंत में उन्होंने सभी उपस्थित अभियंताओं, शिक्षाविदों एवं विद्यार्थियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया।

रात में घर में घुसकर युवती व मां से छेड़छाड़, विरोध पर बेरहमी से पीटा

लालगंज (रायबरेली)। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में देर रात घर में घुसकर युवती और उसकी मां से छेड़छाड़ व मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। युवती ने बताया कि सोमवार देर रात गांव के ही ज्वाला उर्फ सत्यम, अनुज, गुड्डू, अर्पित और गौरव जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि उन्होंने उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने मारपीट की। शोर सुनकर उसकी मां बचाने पहुंची। आरोपियों ने उसके साथ भी बदसलूकी की। उसे बेरहमी से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। किसी तरह मां-बेटी ने खुद को बचाया। पीड़िता का आरोप है कि जाते समय आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि मामले में पांचों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

सभी गो सेवकों की एकजुट पहल—गो सम्मान आह्वान अभियान में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

- इस अभियान की खास बात यह रही कि इसमें किसी भी संगठन विशेष का नाम या बैनर नहीं था

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर। आज तहसील परिसर में उस समय एक अलग ही जोश और उत्साह का माहौल देखने को मिला, जब सभी गो सेवक साथी एवं गोप्रेमी एकजुट होकर 'गो सम्मान आह्वान अभियान' के अंतर्गत तहसीलदार को ज्ञापन पत्र सौंपने पहुंचे। इस अभियान की खास बात यह रही कि इसमें किसी भी संगठन विशेष का नाम या बैनर नहीं था, बल्कि यह पूरी तरह से समर्पित गोसेवकों का सामूहिक प्रयास था। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित गोभक्तों ने गौ माता के संरक्षण, संवर्धन एवं सम्मान को लेकर अपनी भावनाएं प्रकट कीं। सभी ने एक स्वर में गौ रक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और ठोस कदम उठाने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय उपस्थित गोसेवकों में खासा उत्साह देखने को मिला। पूरे वातावरण में 'गौ माता की जय' के जयघोष गूंजते रहे, जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय और ऊर्जा से भर गया। गो सेवकों ने बताया कि यह अभियान किसी संगठन का नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का है जो गौ माता के प्रति श्रद्धा और सेवा का भाव रखता है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि गौवंश की सुरक्षा और सम्मान के लिए जल्द से जल्द प्रभावी निर्णय लिए जाएंगे। इस अवसर पर सभी गोप्रेमियों ने एकजुट होकर आगे भी ऐसे प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया।

भीषण गर्मी में गौ सेवा की अनोखी मिसाल

- गौशाला में शरबत पिलाकर दिया राहत का संदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख (सीतापुर)- चिलचिलाती धूप और लगातार बढ़ते तापमान के बीच जहां आमजन बेहाल हैं, वहीं बेजुबान पशुओं की पीड़ा को समझते हुए वर्मी स्थित कामधेनु गौ आश्रय केंद्र में एक सराहनीय और मानवीय पहल देखने को मिली। ग्राम प्रधान एवं प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में गौशाला में रह रही गायों के लिए शरबत पिलाने की विशेष व्यवस्था की गई, जिससे उन्हें भीषण गर्मी से राहत मिल सके। गौशाला में इस व्यवस्था के तहत नियमित रूप से ठंडे और पौष्टिक शरबत की आपूर्ति की जा रही है, ताकि गायों के शरीर में पानी की कमी न हो और वह लू के प्रकोप से सुरक्षित रह सकें। इसके साथ ही गौशाला परिसर में साफ-सफाई, छायादार स्थान और पर्याप्त पानी की उपलब्धता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस पहल की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में इसकी चर्चा तेज हो गई और स्थानीय लोगों ने ग्राम प्रधान व उनकी टीम की जमकर सराहना की। ग्रामीणों का कहना है कि जिस प्रकार इंसानों के लिए गर्मी में राहत के उपाय किए जाते हैं, उसी तरह पशुओं के लिए भी इस तरह की संवेदनशील पहल समाज के लिए एक प्रेरणा है।प्रधान प्रतिनिधि अमित कश्यप ने बताया कि 'भीषण गर्मी को देखते हुए गौ माता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। इसी भावना के साथ गौशाला में शरबत पिलाने की व्यवस्था की गई है, ताकि उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। आगे भी पशुओं की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। 'उन्होंने यह भी बताया कि गौशाला में समय-समय पर पशु चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाता है, जिससे गायों की सेहत बेहतर बनी रहे। इस पहल से न केवल पशु प्रेमियों में खुशी है, बल्कि यह संदेश भी गया है कि बेजुबान जीवों के प्रति संवेदनशीलता ही सच्ची सेवा है। ग्राम प्रधान और उनकी टीम की यह पहल क्षेत्र में एक मिसाल बनकर उभरी है, जो समाज को मानवता और करुणा का संदेश देती है।

प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में निर्माण कार्य का शुभारंभ

- स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर परिसर में बरामदा निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शुभारंभ किया

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मिश्रिख/ विकास खण्ड गोंदलामऊ में स्थित प्रसिद्ध और प्राचीन मनकामेश्वर महादेव मंदिर के कायाकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। स्थानीय ग्रामीणों और श्रद्धालुओं द्वारा मंदिर परिसर में बरामदा निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया है।

प्राचीन धरोहर को सहेजने की पहल

ग्रामीणों के अनुसार, यह शिव मंदिर काफी पुराना है और आस्था का बड़ा केंद्र है। समय के साथ मंदिर के कुछ हिस्सों को मरम्मत की आवश्यकता थी। अब बरामदे के निर्माण से यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बैठने और विश्राम करने की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। मंदिर कमेटी और सहयोगियों का लक्ष्य है कि इस कार्य को गुणवत्ता के साथ जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा । मन्दिर जिर्णोद्धार में इस पुनीत कार्य को संपन्न कराने में ग्राम के कई गणमान्य व्यक्तियों का विशेष सहयोग मिल रहा है। जिसमें मुख्य रूप से कवि विनीत तिवारी अधिवक्ता, रवि प्रकाश तिवारी ठेकेदार , गौरव तिवारी, दीपक मिश्रा, राकेश तिवारी इन सभी के संयुक्त प्रयासों और सक्रिय सहयोग से निर्माण कार्य को गति दी जा रही है। जीर्णोद्धार कार्य शुरू होने से स्थानीय निवासियों और शिव भक्तों में हर्ष का माहौल है।

कवरेज के बहाने बुलाकर पत्रकार की पिटाई, केस दर्ज

ब्रेकिंग न्यूज़

लालगंज (रायबरेली)। कस्बे के स्टेशन रोड मोहल्ला निवासी एक स्थानीय पत्रकार को सोमवार देर शाम कवरेज के बहाने बुलाकर अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से पीट दिया। हमले में पत्रकार गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मोहल्ला निवासी अभिषेक कुमार बाजपेई ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि सोमवार देर शाम एक अज्ञात नंबर से फोन आया, जिसमें उसे बेलौली गांव के पास बुलाया गया। वह जैसे ही मौके पर पहुंचा, बाइक सवार दो लोगों ने उस पर बिजली के केबल और सरिया से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। आरोपी घटना के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। घायल पत्रकार का इलाज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों की तलाश के लिए जांच की जा रही है।

चिलचिलाती धूप में जहांगीराबाद चौराहे पर पानी का संकट

- प्यास बुझाने को नहीं है कोई हैंडपंप
- गतवर्ष उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने लगाया गया था वाटर कूलर प्वाइंट
- काफी समय से बंद पड़ा वाटर कूलर प्वाइंट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। काफी समय से जहांगीराबाद चौराहे पर तथा उसके आसपास कोई नल न होने से राहगीरों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है लोग प्यास बुझाने के लिये इधर उधर भटकते रहते हैं।इन दिनों भयंकर गर्मी पड़ रही है तथा लू चलने लगी है ऐसे में यहां पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। चौराहे के आसपास कोई भी इण्डिया मार्का नल नहीं है जिससे यहां से गुजरने वाले राहगीरों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं जहांगीराबाद में रेउसा-बिसवां मार्ग पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के सामने गत वर्ष एक वाटर कूलर प्वाइंट लगाया गया था जो कुछ ही दिनों बाद खराब होकर बंद हो गया था जो आजतक ठीक नहीं कराया जा सका है। बैंक उपभोक्ताओं को प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। यह हाल सीतापुर-बहराइच मुख्य मार्ग पर जहांगीराबाद चौराहे का है जहां पूरे चौराहे पर कोई भी इण्डिया मार्का नल नहीं है। काफी समय पहले जिला सहकारी बैंक के निकट एक मात्र इंडिया मार्का नल सड़क किनारे लगा था जो काफी समय तक बंद पड़ा रहा फिर उसे ग्राम पंचायत ने उखड़वा लिया जिस कारण चौराहे पर पानी की भारी किल्लत हो रही है।रोजाना सुबह से रात तक सैकड़ों लोगों को प्यास बुझाने के लिये या तो दुकानों व ठेलों पर बिकने वाली 10 या 20 ? की बोतलों को खरीदना पड़ रहा है अथवा चाय मिठाई की दुकानों में झांकना पड़ रहा है। जहांगीराबाद कस्बे से प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों का लखनऊ, महमूदाबाद, सीतापुर, दिल्ली, बहराइच, रेउसा व तम्बौर आदि नगरों की ओर आना जाना रहता है जो जहांगीराबाद चौराहे से ही विभिन्न साधनों द्वारा अपने गंतव्य तक जाते हैं। चौराहे पर प्यास लगने पर उन्हें भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। यहां गांव में तीन बैंक शाखाएं भी हैं जहां प्रतिदिन सैकड़ों लोगों का आना जाना रहता है।गांव तथा क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने नल लगवाये जाने की मांग की है। इस सम्बन्ध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि मुनीर अहमद अंसारी ने कहा कि यह समस्या मेरी जानकारी में हैं। जल्द ही पीने के पानी की व्यवस्था सही करायी जायेगी। पन्द्रह दिनों के अन्दर दोनों समस्याओं का समाधान करा दिया जायेगा। इस बारे में ग्राम विकास अधिकारी शैलेन्द्र कुमार भार्गव ने बताया कि जगह मिलते ही जल्द से जल्द नया नल लगवा कर पेयजल की समस्या का समाधान कर दिया जायेगा। बैंक के सामने वाटर कूलर के बंद होने के सम्बन्ध में बताया कि बोरिंग से बालू आने लगी थी जिससे फिल्टर खराब हो गये हैं। इसके अतिरिक्त बिजली की भी समस्या है। इसलिए अभी तक यह वाटर प्वाइंट शुरू नहीं हो सका है। वहां पर इसे हटवाकर जल्द ही दूसरा इण्डिया मार्का हैंडपंप लगवा दिया जायेगा।

प्रेरक कहानी का वीडियो देखकर बच्चों ने जाना संघर्ष का मतलब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज (रायबरेली)। क्षेत्र के ऐहार स्थित श्री गणेश विद्यालय इंटर कॉलेज में मंगलवार को जूनियर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक शैक्षिक गतिविधि आयोजित की गई। इसमें कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रधानाचार्य अवनींद्र पांडे के निर्देशन में छात्रों को बिहार प्रान्त के एक संघर्षशील बालक की सफलता की कहानी वीडियो के माध्यम से दिखाई गई। बालक बेहद गरीब परिवार से है। उसने हालात से हार नहीं मानी। मेहनत और आत्मविश्वास के दम पर आगे बढ़ा। कहानी में कक्षा 3 में पढ़ने वाले इस बच्चे ने कक्षा 10 तक के छात्रों को गणित पढ़ाकर अपने परिवार की आर्थिक मदद की। उसकी लगन और हिम्मत ने बच्चों को गहराई से प्रभावित किया। वीडियो के बाद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ। संचालन शिक्षक डॉ. कमलाकांत ने किया। उन्होंने बच्चों से सवाल पूछे और उनकी समझ और सोचने की क्षमता को परखा। कार्यक्रम के बाद बच्चों में खासा उत्साह दिखाई दिया।उन्होंने सीखा कि कठिनाई रास्ता नहीं रोकती, बल्कि मजबूत बनाती है। प्रबंधक कार्तिकेय शंकर वाजपेई ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विद्यालय प्रबंधन ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां नियमित रूप से कराई जा रही हैं। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है।

अल्पसंख्यक आयोग की नियुक्ति में देरी पर हाई कोर्ट नाराज

लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जाहिर की है। न्यायालय ने कहा कि पूर्व आयोग का कार्यकाल 2024 में ही समाप्त हो चुका है, इसके बावजूद नई नियुक्तियों को लेकर प्रतिवादियों की स्पष्ट निष्क्रियता साफ दिखाई दे रही है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि नियत करते हुए, राज्य सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में स्पष्ट जवाब देने का आदेश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली व न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने शम्स तबरेज की जनहित याचिका पर पारित किया है। याचिका में आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की शीघ्र नियुक्ति के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि आयोग में नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस पर न्यायालय ने कहा कि चार फरवरी को पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने बताया था कि प्रक्रिया चल रही है लेकिन आज तक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक पूरी स्थिति स्पष्ट करने निर्देश दिए हैं।

राकेश सचान ने विकास कार्यों व कानून-व्यवस्था की समीक्षा बैठक कर दिए निर्देश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

रायबरेली:- मंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम,खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा तथा वस्त्रोद्योग विभाग उ0प्र0/प्रभारी मंत्री जनपद राकेश सचान ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ कानून-व्यवस्था की स्थिति एवं विकास कार्यों की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि यह सुनिश्चित कराया जायें कि कोई पात्र व्यक्ति आवास से वंचित न रहें। निराश्रित गोवंश की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि गर्मी के दृष्टिगत पशुओं को लू/हीटवेव से बचाव हेतु सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराया जाये। शत प्रतिशत निराश्रित गोवंशों को आश्रित कराया जायें, गोशालाओं में हरे चारे, छाया आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए, गोवंश सहभागिता योजना के अन्तर्गत लोगों को प्रेरित कर अधिक से अधिक गोवंशों की सुपुर्दगी करायें। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को शीघ्र ही पूर्ण कराया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में अधिक से अधिक जोड़ों का रजिस्ट्रेशन कराकर लाभान्वित कराया जाए। प्रभारी मंत्री ने आयुष्मान कार्ड की समीक्षा में निर्देश दिये कि पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड बनवाया जायें। किसानों को सिंचाई हेतु नहरों में टेल तक पानी पहुंचाने के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित कराया जाए, जिससे किसानों को फसल सिंचाई में कोई दिक्कत न हो, किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए विद्युत आपूर्ति भी रोस्टर के अनुसार सुनिश्चित करायी जायें। ग्रामीण क्षेत्रों में जले हुए ट्रांसफार्मर को निर्धारित समय में रिप्लेस कराया जाए। पीएमजीवाई विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि सड़कों की नवीनीकरण/मरम्मत कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाए, इसके साथ ही निर्माणकार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित कराई जाए। सभी विभाग अपने लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करायें, विगत वित्तीय वर्ष के निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि माह मई तक कार्य योजना तैयार कर अक्टूबर एवं नवम्बर तक कार्यों को नियमानुसार पूर्ण करा लिया जाए। इस अवसर पर मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत रंजना चौधरी, जिलाधिकारी सरनीत कौर ब्रोका, पुलिस अधीक्षक रवि कुमार, मुख्य विकास अधिकारी अंजूलता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 नवीन चन्द्रा, अपर जिलाधिकारी (वि0रा0) अमृता सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार, परियोजना निदेशक डीआरडीए सतीश प्रसाद मिश्रा सहित सभी संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।

संक्षिप्त खबरें

विपक्ष को घेरने की तैयारी! योगी सरकार ने बुलाया विशेष सत्र

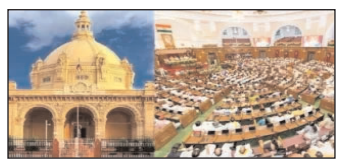

लखनऊ। परिसीमन के साथ नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक लोक सभा में पारित नहीं होने के मामले में अब प्रदेश में इस पर चर्चा के लिए 30 अप्रैल को विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें महिला सशक्तीकरण पर दोनों ही सदनों में अनवरत चर्चा होगी। इस विशेष सत्र में महिलाओं को ही बोलने का ज्यादा मौका दिया जाएगा। 18वीं विधान सभा में कुल 51 महिला सदस्य हैं, इनमें सर्वाधिक 30 सदस्य भाजपा की हैं। सपा की 15, अपना दल की चार, कांग्रेस व रालोद की एक-एक महिला सदस्य हैं। वहीं, 100 सीटों वाली विधान परिषद में मात्र चार महिला सदस्य हैं। इनमें तीन भाजपा व एक निर्दलीय हैं। यूं तो बुधवार 29 अप्रैल को विधान सभा व विधान परिषद की कार्यमंत्रणा समिति की अलग-अलग बैठक में विशेष सत्र का बिजनेस तय होगा, किंतु इतना तय माना जा रहा है कि महिला सदस्यों को ही बोलने का अधिक मौका दिया जाएगा। सूत्रों के अनुसार सबसे पहले संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना सदन में महिला सशक्तीकरण पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष व दलीय नेता भी इस पर अपने विचार रखेंगे। भाजपा की कोशिश यही है कि इस पर अधिक से अधिक महिला सदस्य ही बोलें। अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विषय पर अपनी बात रखेंगे और महिलाओं के लिए डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाएंगे। भाजपा महिला आरक्षण पर विपक्ष खासकर कांग्रेस व सपा को घेरेगी। वहीं, शीतकालीन सत्र से लेकर अब तक सरकार छह अध्यादेश पास कर चुकी है। इनमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता संशोधन अध्यादेश, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता द्वितीय संशोधन अध्यादेश, उप्र वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, उप्र दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) संशोधन अध्यादेश तथा उप्र निजी विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश शामिल हैं। इन सभी अध्यादेश की जानकारी सरकार सदन को देगी।

यूपी पंचायत चुनाव में देरी होने पर सामने आने लगी अनोखी मांग

लखनऊ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाने की तस्वीर साफ होते ही पंचायत प्रतिनिधियों की बेचैनी बढ़ गई है। मंगलवार को योजनाओं की जानकारी देने के लिए आयोजित क्षेत्र पंचायत प्रमुखों कार्यशाला पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने का अखाड़ा नजर आया। जिसके बाद मंच से पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष रखा जाएगा। पूरी कोशिश होगी कि सरकार कार्यकाल बढ़ाने पर राजी हो जाए। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को करना है। पंचायती राज निदेशालय में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के लिए आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मंत्री ने प्रमुखों से कहा कि मैं आप लोगों की भावनाओं को समझ रहा हूं, इसका कद्र किया जाएगा। कार्यकाल बढ़ाने के लिए आप लोगों की बातें मुख्यमंत्री के समक्ष पूरी ताकत के साथ रखने का काम होगा। उन्होंने ब्लाक प्रमुख संघ से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रशासक समिति के गठन के माध्यम से कार्यकाल बढ़ाए जाने के लिए जारी आदेशों की प्रति के साथ प्रस्ताव देने को कहा। प्रमुखों को आश्वासन दिया कि जल्द ही 10 लाख की जगह 15 लाख रुपये तक की योजनाओं को स्वीकृत करने का अधिकार उन्हें दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री के जिले में पहुंचने की सूचना प्रमुखों को भी मिले इसकी व्यवस्था की जाएगी। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पंचायत चुनाव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है।हाईकोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। हम पंचायत चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम स्थल पर मंत्री के पहुंचने से पहले मंच से ब्लाक प्रमुख प्रमुख संघ उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने प्रमुख सचिव अनिल कुमार से कार्यकाल समाप्त होने पर मौजूदा क्षेत्र पंचायतों को ही प्रशासक नियुक्त करने की मांग की। राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड की तरह प्रशासक समिति का गठन करने का सुझाव दिया। मंच से पदाधिकारी कार्यकाल बढ़ाने का मुद्दा पूरे दमखम से रखें इसके लिए हाल में बैठे प्रमुखों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बहस भी हुई। दबाव बनाया कि सिर्फ कार्यकाल बढ़ाने पर ही बात हो। संघ के प्रदेश अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह 'सेनानी' के संबोधन के दौरान इस कदर टोका टोकी की गई कि उन्हें कहना पड़ा कि जो अपने को अधिक सक्षम समझ रहा है, वह मंच पर आ जाए।

आंध्र प्रदेश में खुलेगा गूगल डेटा सेंटर

● 15 अरब डॉलर के निवेश से बनेगा AI हब; हजारों नौकरियों के अवसर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम के पास 15 अरब डालर (लगभग 1.35 लाख करोड़ रुपये) के गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा सेंटर का शिलान्यास किया और कहा कि यह भारत के लिए एक विकास इंजन होगा। मुख्यमंत्री ने इस गूगल डाटा सेंटर को एशिया की सबसे बड़ी ऐसी सुविधा बताया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह डाटा सेंटर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब के रूप में उभरेगा।

15 अरब डॉलर का गूगल डाटा सेंटर

विशाखापत्तनम के तारलुवाड़ा में गूगल क्लाउड इंडिया एआइ डेटा सेंटर के शिलान्यास समारोह में मंगलवार को नायडू ने कहा कि एक गीगावाट क्षमता वाला डाटा सेंटर भारत की डिजिटल संरचना विकास में महत्वपूर्ण कदम के रूप में उभरेगा। यह देश के सबसे बड़े एआइ डाटा सेंटर में से एक होने की उम्मीद है और उन्नत एआइ क्लाउड अवसंरचना और बड़े पैमाने पर डाटा भंडारण क्षमताएं प्रदान करेगा। हालांकि राज्य सरकार ने 6.5 गीगावाट की कुल क्षमता के साथ 'मल्टी-गीगावाट डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र' विकसित करने के लिए दीर्घकालिक योजना बनाई है। नायडू ने कहा कि यह परियोजना सितंबर, 2025 में शुरू की गई थी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इसे 28 सितंबर, 2028 को उद्घाटन करेंगे। उन्होंने सभी हितधारकों से अपील की कि वे समय सीमा (23 सितंबर, 2028) से छह महीने पहले इस सुविधा का निर्माण पूरा करें। मुख्यमंत्री के अनुसार, गूगल डेटा सेंटर युवाओं के लिए हजारों नौकरियों का सृजन करेगा। यह सुविधा तारलुवाड़ा, अदविवरम और रामबिली गांवों में 600 एकड़ में स्थापित होगी।

'हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु बुलेट ट्रेन से जुड़ेंगे'

मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि रेलमंत्री वैष्णव ने लगभग सात से आठ वर्षों में चार दक्षिण भारतीय शहरों को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का वादा किया है। उन्होंने संकेत दिया कि बुलेट ट्रेन से हैदराबाद, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों और अमरावती के ग्रीनफील्ड शहर को केवल एक घंटा व 10 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। भोगापुरम हवाई अड्डे का उद्घाटन जुलाई में पीएम मोदी करेंगे। विशाखापत्तनम से 60 किमी पूर्वोत्तर में स्थित भोगापुरम गांव में हवाई अड्डा जीएमआर समूह बना रहा है।

देश में सर्वर, चिप्स के निर्माण का आग्रह

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश आइटी सेवाओं में अग्रणी देश के रूप में उभरा है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर निर्माण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने आइटी कंपनियों से देश में सर्वर, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) और चिप्स का निर्माण करने का आग्रह किया और इसे गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई तक पहुंचाने का अनुरोध किया। वैष्णव ने विशाखापत्तनम से समुद्री केबल बिछाने के लिए गूगल का धन्यवाद किया, जो यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका व अमेरिका को जोड़ने वाली वैश्विक कनेक्टिविटी बढ़ाएगा।

बड़ा बाजार में अतिक्रमण हटाया

● लंबे कानूनी संघर्ष के बाद जिले के दुल्लभछड़ा में अतिक्रमण हटाया

●परिवार को जमीन वापस मिली

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि– लंबे समय से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा के बड़ा बाजार क्षेत्र में एक परिवार को उसकी अपनी जमीन वापस मिल गई। प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर संबंधित जमीन को कब्जामुक्त कराया गया। सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2007 में श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुल्लभछड़ा बड़ा बाजार के बेणुरंजन देव और अब्दुल हमीद के बीच जमीन को लेकर मामला जिला अदालत में दायर किया गया था। यह मामला बेणुरंजन देव द्वारा दर्ज कराया गया था। उनका आरोप था कि अब्दुल हमीद ने उनकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लंबे समय से उसका उपयोग किया। लंबे समय तक दोनों पक्षों के साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर सुनवाई चलने के बाद हाल ही में अदालत ने बेणुरंजन देव के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद गत 27 अप्रैल, सोमवार की शाम पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से उक्त जमीन पर बने अब्दुल हमीद के अवैध मकान को ध्वस्त कर दिया गया और जमीन वास्तविक मालिक को सौंप दी गई। हालांकि, संपर्क न हो पाने के कारण इस मामले में दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हो सकी।

रूस-चीन के सामने फीकी पड़ी अमेरिका की ताकत

● हाइपरसोनिक मिसाइलों का नहीं कोई तोड़

ईरान युद्ध के बीच पेंटागन का बड़ा कबूलनामा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। अमेरिका में एक सीनियर पेंटागन अधिकारी ने कांग्रेस (अमेरिकी संसद) की सुनवाई के दौरान माना कि अमेरिकी सेना के पास अभी रूस और चीन जैसे दुश्मनों के हाइपरसोनिक हथियारों या एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों के खिलाफ कोई डिफेंस लाइन नहीं है। अमेरिका की स्पेस पॉलिसी के लिए युद्ध के असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्क बर्कविट्ज अमेरिकी सीनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सामने अगली पीढ़ी के 'गोल्डन डोम' मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर सुनवाई के दौरान बोल रहे थे, जिसे अमेरिका में विकसित किया जा रहा है।

अमेरिका के पास नहीं रूस-चीन से लड़ने की ताकत

अमेरिका की स्पेस पॉलिसी के लिए युद्ध के असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्क बर्कविट्ज ने अमेरिकी सीनेट को यह भी बताया कि दुश्मन देश अब 'नॉन-बैलिस्टिक खतरे' विकसित कर रहे हैं, जिनमें हाइपरसोनिक और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें शामिल हैं, जिन्हें अमेरिका को खतरे में डालने के लिए डिजाइन किया गया है। मार्क बर्कविट्ज से अमेरिका की मौजूदा मिसाइल डिफेंस क्षमताओं के बारे में बताने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा, 'आज, हमारे पास जमीन पर आधारित एक बहुत ही सीमित, सिंगल-लेयर होमलैंड डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर उत्तर कोरिया से होने वाले छोटे पैमाने के हमले के खिलाफ डिजाइन किया गया था।' मार्क बर्कविट्ज ने आगे बताया, 'हमारे पास किसी भी अन्य बैलिस्टिक मिसाइल हमले का मुकाबला करने की बहुत सीमित क्षमताएं हैं। अगर हम एडवांस्ड क्रूज मिसाइलों की बात करें तो आज हमारे पास हाइपरसोनिक हथियारों या क्रूज मिसाइलों के खिलाफ भी कोई डिफेंस नहीं है।' यह कड़ा आकलन चीन, रूस, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों की बढ़ती सैन्य क्षमताओं को लेकर चिंताओं के बीच आया है, जिससे वॉशिंगटन को अपने होमलैंड मिसाइल डिफेंस में बड़ी कमियों को स्वीकार करने पर मजबूर होना पड़ा है।

यूपी के किसानों के खाते में अगले महीने आएंगे 122.28 करोड़ रुपये

लखनऊ। खराब मौसम से फसल नुकसान झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार चार मई को 122.28 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि उनके खातों में भेजेगी। यह भुगतान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किया जाएगा। इसमें खरीफ 2025 के बकाया 105.16 करोड़ रुपये और रबी 2025-26 के 17.11 करोड़ रुपये शामिल हैं। खरीफ 2025 के लिए कुल 730.04 करोड़ रुपये देय थे, जिसमें से 624.88 करोड़ रुपये पहले ही दिए जा चुके हैं। इससे पहले 21 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'वन-क्लिक' के जरिए 285 करोड़ रुपये 2.51 लाख किसानों को दिए थे। 2017-18 से अब तक 67.86 लाख किसानों को 5755.68 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति मिल चुकी है। योजना में धान, गेहूं, दालें, तिलहन और आलू जैसी फसलें शामिल हैं। किसानों को कम प्रीमियम देना पड़ता है। जो खरीफ पर दो प्रतिशत, रबी पर 1.5 प्रतिशत और नकदी फसलों पर अधिकतम पांच प्रतिशत है, बाकी खर्च सरकार उठाती है। कृषि सांख्यिकी एवं फसल निदेशक बीमा सुमिता सिंह के अनुसार, प्रदेश के सभी जिलों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से यह राशि वितरित की जाएगी।

सोनी पल पर शुरू हो रही साहस और भक्ति के प्रतीक 'संकट मोचन हनुमान

● इस धारावाहिक की शानदार स्टार कास्ट ने इन पौराणिक किरदारों को पूरी सच्चाई और जीवंतता के साथ पर्दे पर उतारने का काम किया है।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

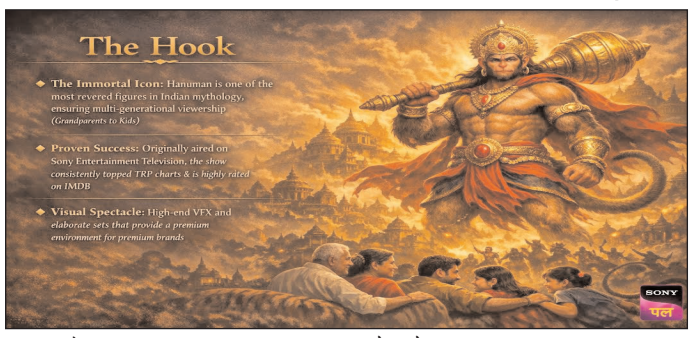

दया शंकर त्रिपाठी की रिपोर्ट

ब्यूरो प्रयागराज। भारत का लोकप्रिय एंटरटेनमेंट चैनल सोनी पल, जो अलग-अलग प्रकार के कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है, ने गर्व और उत्साह के साथ संकट मोचन हनुमान के प्रसारण की घोषणा की है। यह एक कालजयी पौराणिक धारावाहिक है, जो पीढ़ियों से लोगों को प्रेरित करता रहा है। सोनी पल पर इसके शुरू होने के साथ दर्शकों को भगवान हनुमान की साहसिक यात्रा को एक बार फिर नए अंदाज में देखने का अवसर मिलेगा। इस महाकाव्य के केंद्र में भक्ति, शक्ति और साहस के सच्चे 'सुपरहीरो' भगवान हनुमान हैं। उनकी जीवन यात्रा वीरता और अटूट निष्ठा से भरी है, जो हर पीढ़ी के दर्शकों को गहराई से जोड़ती है और उन्हें आस्था, धर्म व निस्वार्थ सेवा जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाती है। यह कहानी भगवान हनुमान की उस अद्भुत यात्रा को दिखाती है, जहाँ वे निडर रक्षक के रूप में सामने आते हैं। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति असीम है और बुराई के खिलाफ उनका साहस बेजोड़ है।

शानदार दृश्यों और दमदार कहानी के साथ यह सिर्फ एक धारावाहिक नहीं, बल्कि एक प्रेरणादायक अनुभव है, जो दिल और आत्मा को छू जाता है। इस धारावाहिक की शानदार स्टार कास्ट ने इन पौराणिक किरदारों को पूरी सच्चाई और जीवंतता के साथ पर्दे पर उतारने का काम किया है। गगन मलिक भगवान राम के रूप में गरिमा और मर्यादा को दर्शाते हैं; देब्लिना चटर्जी, माता सीता की करुणा और शक्ति को खूबसूरती से प्रस्तुत करती हैं। वहीं निर्भय वाधवा भगवान हनुमान की दिव्य ऊर्जा को जीवंत करते हैं और सौरव गुर्जर रावण के रूप में दमदार अभिनय करते नजर आते हैं। ये सभी कलाकार मिलकर एक ऐसी दुनिया रचते हैं, जो जादुई होने के साथ-साथ हमारी परंपराओं से गहराई से जुड़ी हुई है। भगवान हनुमान को परम रक्षक और दिव्य सुपरहीरो के रूप में प्रस्तुत करने वाला संकट मोचन हनुमान, अपने शाश्वत संदेश और यादगार अभिनय से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने का वादा करता है। सोनी पल दर्शकों को इस दिव्य यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है, जहाँ भगवान हनुमान की गाथा एक बार फिर टीवी स्क्रीन पर लौट रही है, जो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, प्रेरणादायक और प्रासंगिक है। यह शो 4 मई से रात 9 बजे, दर्शकों को हनुमान जी की कहानी को फिर से जीने और भक्ति की भावना को दोबारा महसूस करने का मौका देगा।

माहौल बिगाड़ने की राजनीति में जुटी सपा,अखिलेश यादव के बयान पर श्रम मंत्री का पलटवार

लखनऊ। गाजीपुर में युवती की मौत के मामले में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सपा पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। कहा कि सपा और उसके मुखिया संवेदनशील मामलों में भी राजनीति करने से पीछे नहीं हटते। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा पूर्वांचल का सामाजिक माहौल खराब करने में लगी हुई है। मंत्री ने कहा कि सपा की गिद्ध नजर हमेशा ऐसे मामलों पर रहती है, जहां से राजनीतिक फायदा लिया जा सके। सपा का मकसद पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना नहीं, बल्कि समाज में तनाव पैदा कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित युवती के पिता स्वयं हाथ जोड़कर अपील कर चुके हैं कि उनकी बेटी की मौत पर राजनीति न की जाए। पीड़ित परिवार सरकार और प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट है तथा मामले में लगातार निगरानी रखी जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। माहौल खराब करने वालों, अफवाह फैलाने वालों और शांति भंग की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा में भीषण आग

● मवेशियों को बचाने में सदानंद सिन्हा गंभीर रूप से झुलसे

●इलाके में दहशत, फायर ब्रिगेड स्टेशन की मांग को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: श्रीभूमि जिले के रामकृष्णनगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत दुल्लभछड़ा के पास स्थित आदर्श कृष्णनगर गांव में एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। सी.वी.पी. स्कूल के पूर्व दिशा में स्थित पूर्व पत्रकार जगदानंद सिन्हा के गौशाला में बीती रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने गौशाला के विभिन्न हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही जगदानंद सिन्हा के बड़े भाई सदानंद सिन्हा मवेशियों को बचाने के लिए आगे बढ़े। इस दौरान वे गंभीर रूप से झुलस गए। बताया जा रहा है कि उनके शरीर का अधिकांश हिस्सा आग में जल गया है। परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत नजदीकी दुल्लभछड़ा अस्पताल ले जाया गया। लेकिन वहां पर्याप्त उपचार सुविधा न होने के कारण उनकी हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद उन्हें सिलचर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया। संचार संबंधी समस्याओं के चलते बाद में उन्हें आनन-फानन में माकुंदा अस्पताल स्थानांतरित किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इधर, आग की खबर फैलते ही रात करीब 2:30 बजे स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। बाद में रात 2:45 बजे राताबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। रामकृष्णनगर फायर सर्विस विद्यानगर के रास्ते रात 3:15 बजे घटनास्थल पर पहुंचकर आग को पूरी तरह नियंत्रित किया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और घटना की जांच जारी है। उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में क्षेत्र में कई अग्निकांड की घटनाओं से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी को लेकर स्थानीय निवासियों ने दुल्लभछड़ा में शीघ्र फायर ब्रिगेड स्टेशन स्थापित करने की मांग करते हुए प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है।

पटना में NEET की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या

हॉस्टल के रूम से मिला सुसाइड नोट

पटना। एसके पुरी थाना क्षेत्र के नागेश्वर पथ स्थित एक हॉस्टल (नालंदा रेसीडेंसी) में नीट (NEET) की तैयारी कर रहे मुजफ्फरपुर के छात्र श्रेयम ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दो साल से अपार्टमेंट में रहने वाले श्रेयम के शव के पास से डिब्बा और सुसाइड नोट मिला। रूममेट परीक्षा के लिए घर गया है। बगल के छात्र अंश ने बताया, पिछले 3 दिनों से वह असामान्य रूप से शांत था। कल देर रात तक बातचीत सुनाई दी। सुबह दरवाजा न खुलने पर तोड़ा तो बेड पर लाश मिली। हॉस्टल मालिक के अनुसार वह दो साल से रह रहा था। फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची थी।

थानों में सीसीटीवी के लिए फंड के इस्तेमाल के मुद्दे पर बैठक बुलाए केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

● राज्यों द्वारा फंड के इस्तेमाल के पहलू पर विचार-विमर्श करने के लिए छह मई को एक बैठक बुलाई जाए

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि देशभर के पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के लिए राज्यों द्वारा फंड के इस्तेमाल के पहलू पर विचार-विमर्श करने के लिए छह मई को एक बैठक बुलाई जाए। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने अमिकस क्यूरी और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ देव से कहा कि केंद्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक करें। पीठ ने कहा- 'हम चाहते हैं कि अमिकस द्वारा आयोजित की जाने वाली बैठक में केंद्रीय गृह सचिव या उनके नामित व्यक्ति और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के गृह सचिव भाग लेंगे।' यह मुद्दा तब सामने आया जब देव ने राज्यों द्वारा फंड के उपयोग का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र 100 प्रतिशत फंड देता है, जबकि पहाड़ी राज्यों में 90 प्रतिशत और अन्य राज्यों में 60 प्रतिशत फंड केंद्र द्वारा दिया जाता है। पीठ ने कहा- ''राज्यों से फंड के उपयोग पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं मिल रही है?' शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया कि अमिकस इस मुद्दे पर केंद्र, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ बैठक बुला सकता है। मामले की सुनवाई अगली सुनवाई 13 मई को होगी और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

पंजाब में आया 150 की रफ्तार से बॉलिंग करने वाला गेंदबाज

● राजस्थान ने तूफानी बल्लेबाज को किया बाहर

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने मंगलवार को मुल्लांपुर में खेले जा रहे आईपीएल-2026 के मैच में मेजबान पंजाब किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मैच में दोनों टीमों ने दो-दो बदलाव किए हैं। पंजाब ने अभी तक एक भी मैच नहीं गंवाया है। उसने सात मैच खेले हैं जिसमें से छह में उसे जीत मिली है तो वहीं एक मैच रद हुआ है। वहीं राजस्थान ने आठ मैचों में से पांच में जीत और तीन में हार झेली है। इस मैच में राजस्थान पंजाब के विजयी रथ को रोकना चाहेगी।

पंजाब ने दिया तूफानी गेंदबाज को मौका

पंजाब की टीम ने इस मैच में दो बदलाव किए हैं। लगातार अपनी फील्डिंग से निराश करने वाले शशांक सिंह को बाहर किया गया है। उनकी जगह सूर्यांश शेडगे आए हैं। एक और बदलाव टीम ने किया है। तेज गेंदबाज जेवियर बार्टलेट को बाहर जाना पड़ा है। उनकी जगह लॉकी फर्ग्यूसन टीम में आए हैं जो लगातार 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकने का दम रखते हैं। उन्होंने आईपीएल में गुजरात टाइटंस से खेलते हुए 157 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी। ऐसे में राजस्थान के बल्लेबाजों के लिए उनका सामना करना आसान नहीं होगा। देखना होगा कि 15 साल के वैभव सूर्यवंशी इस तूफानी गेंदबाज का सामना कैसे करते हैं।

राजस्थान ने भी किए दो बदलाव

वहीं राजस्थान ने भी अपनी प्लेइंग-11 में दो बदलाव किए हैं। उसने फॉर्म से जूझ रहे तूफानी बल्लेबाज शिमरॉन हेटमायर को बाहर का रास्ता दिखाया है। उनकी जगह श्रीलंका के दासुन शनाका आए हैं। वहीं रवि बिश्नोई की जगह यश पुंजा को मौका दिया है।

भारी तनाव से गुजर रहा देश की एयरलाइन इंडस्ट्री

● सरकार से ATF सस्ता करने की लगाई गुहार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

एअर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने सरकार से एटीएफ (जेट ईंधन) सस्ता करने और संचालन को सुचारु रूप से चालू रखने के लिए वित्तीय मदद मांगी है। एटीएफ विमानन कंपनी के परिचालन खर्च का लगभग 40 प्रतिशत होता है। पश्चिम एशिया में उथल-पुथल ने तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है। साथ ही, एयरस्पेस पर पाबंदियों ने विमानन कंपनियों की परिचालन लागत (खासकर लंबी दूरी के मार्गों पर) बढ़ा दी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (एफआइए) ने नागर विमानन मंत्रालय से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों तरह के संचालन में एक जैसी फ्यूल प्राइसिंग सिस्टम लागू करने को कहा है।

जेट फ्यूल की कीमतों में वृद्धि से विमानन कंपनियों को नुकसान-फेडरेशन

फेडरेशन ने कहा कि जेट फ्यूल की कीमतों में बहुत ज्यादा वृद्धि और क्रूड व एटीएफ के बीच ज्यादा अंतर होने से विमानन कंपनियों का संचालन चुनौतीपूर्ण हो गया है। फेडरेशन ने कहा, 'एटीएफ की कीमत में बिना वजह वृद्धि से एयरलाइंस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इससे विमानों को खड़ा करने की नौबत आ जाएगी। ' 26 अप्रैल को लिखे पत्र में फेडरेशन ने कहा, 'ऑपरेशन जारी रखने और मौजूदा हालात से निपटने के लिए हम सरकार से तुरंत वित्तीय मदद की गुजारिश करते हैं।' साथ ही, फेडरेशन ने एटीएफ पर 11 प्रतिशत उत्पाद शुल्क को कुछ समय के लिए खत्म करने की मांग की है।

दिल्ली में जेट फ्यूल पर 25 तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा 29% का वैट

पिछले महीने, सरकार ने घरेलू संचालन के लिए एटीएफ की कीमत में वृद्धि को 15 रुपये प्रति लीटर तक सीमित कर दिया था। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय संचालन के लिए कीमत 73 रुपये प्रति लीटर तक बढ़ा दी गई थी।

विमानन कंपनियों ने कहा कि इस फैसले से घरेलू संचालन के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय परिचालन को भी काफी नुकसान हुआ है और अप्रैल में विमानन क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है। एफआइए के मुताबिक, देश के सबसे बड़े विमानन हब दिल्ली में जेट फ्यूल पर दूसरा सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत का वैट लगता है जबकि तमिलनाडु में यह सबसे ज्यादा 29 प्रतिशत है। दूसरे बड़े शहर, जैसे मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद और कोलकाता में यह 16 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के बीच है। ये छह शहर भारत में विमानन क्षेत्र के 50 प्रतिशत से ज्यादा ऑपरेशंस को कवर करते हैं।